17 सितंबर, 2026 गुरूवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 168

RNI No. DELMUL/2012/47011

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

30 की उम्र में भी जगब की फिट है स्मृति मंधाना 07

संक्षिप्त वार्ता

आखिर ऐसा करके अल्पसंख्यकों को किस तरह का संदेश दे रही सरकार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की आईपीएस अधिकारी डॉ. बुशरा बानो के तबादले को लेकर विवाद शुरू हो गया है। खड़गपुर की एडिशनल एसपी के पद पर तैनात बानो को राज्य सशस्त्र पुलिस की चौथी बटालियन में डिप्टी कमांडेंट बनाया गया है। उनका तबादला 14 सितंबर को

हुआ, जबकि इसके एक दिन पहले 13 सितंबर को उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें वह यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का उत्साह बढ़ाती नजर आई थीं। वीडियो में डॉ बानो अस्सलामुअलैकुम, इंशाअल्लाह और जजाकल्लाह कहती नजर आईं जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। हिंदू लीगल फंड नाम के एक एक्स अकाउंट ने दावा किया कि इस मामले में पश्चिम बंगाल के गृह सचिव से शिकायत की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि एक सरकारी अधिकारी को सार्वजनिक संवाद में निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए और जय हिंद या वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए।

इस पर पूर्व क्रिकेटर और सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बानो के तबादले पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह चिंताजनक है कि अस्सलाम वालेकुम और इंशाल्लाह कहने पर किसी आईपीएस अधिकारी का तबादला किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी लोक सेवक के अभिवादन को कार्रवाई का आधार बनाया जाता है तो इससे अल्पसंख्यकों को किस तरह का संदेश सरकार देना चाह रही है।

नेपाल में तीन घंटे के भीतर दो बार भूकंप

मुगु में 4.5 और 4.2 तीव्रता के झटके

काठमांडू। उत्तर-पश्चिमी नेपाल में बुधवार तड़के लगातार दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीन घंटे के भीतर आए इन दोनों भूकंपों के कारण स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि, शुरूआती जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं है।

राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र के अनुसार पहला भूकंप रात 1 बजकर 51 मिनट पर दर्ज किया गया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4 .5 रही। भूकंप का केंद्र मुगु जिले के कलाई क्षेत्र के आसपास बताया गया।

इसके करीब ढाई घंटे बाद सुबह 4 बजकर 28 मिनट पर दूसरी बार धरती कांपी। इस भूकंप की तीव्रता 4 .2 मापी गई। इसका केंद्र भी मुगु जिले के आसपास ही बताया गया। दोनों झटके पड़ोसी जिलों डोल्पा और जुमला के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए।

नेपाल भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है और यहां समय-समय पर भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारी

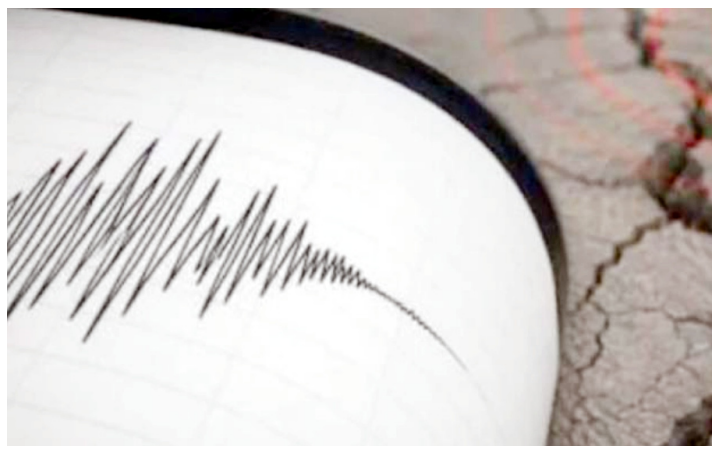

प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। संभावित आफ्टरशॉक और किसी तरह के ढांचागत नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है।

फिलहाल दोनों भूकंपों के बाद किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर स्थिति पर निगरानी जारी रखी है। लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने और भूकंप के दौरान सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरतने की अपील की गई है।

नेपाल में हाल के दिनों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी चिंता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में तड़के आए दो भूकंपों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। हालांकि, वर्तमान स्थिति में किसी बड़ी क्षति की पुष्टि नहीं हुई है।

पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर बप्पा के दर्शन किए

नई दिल्ली। गणपति उत्सव के पावन अवसर पर देश के बड़े राजनेताओं ने श्रद्धा और उल्लास के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश के दर्शन किए और देशवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नई दिल्ली स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और आरती उतारी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। उन्होंने धोती-कुर्ता और सिर पर महाराष्ट्र की पारंपरिक टोपी धारण कर रखी थी।

फार्म हाउस में मेरी हत्या की साजिश रची गई, चंद्रशेखर आजाद का दावा

लखनऊ। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अपनी हत्या की साजिश रचे जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि एक फार्म हाउस में उनकी हत्या की योजना बनाई गई थी। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सरकार से मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनके दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। चंद्रशेखर आजाद ने वीडियो में कहा कि वह यह बात जिम्मेदारी से कह रहे हैं और उनके पास इस संबंध में सूचनाएं और स्रोत हैं। उन्होंने मांग की कि कथित हत्या की साजिश के साथ-साथ बाराबंकी में हुई घटना में शामिल लोगों की भूमिका की भी जांच की जाए।

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में जल्द होगा क्रिकेट का 'शंखनाद'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जल्द ही क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी के गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का कार्य तेजी से चल रहा है।

अगले साल 2027 में यह जनवरी से लेकर मार्च तक महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग के मुकाबलों की मेजबानी करेगा।

बुधवार को हुई डब्ल्यूपीएल संचालन परिषद की बैठक में अगले सत्र के लिए वाराणसी के अलावा मुंबई के सीसीआई और वडोदरा को आयोजन स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया है। बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, स्टेडियम को पूरी तरह तैयार होने के बाद सबसे पहले अक्टूबर-नवंबर में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला कराया जा सकता है।

रणजी और डब्ल्यूपीएल के बाद होंगे इंटरनेशनल मुकाबले

रणजी का मुकाबला होने के बाद इस स्टेडियम को महिला प्रीमियर लीग के लिए तैयार किया जाएगा। आगामी सत्र में जनवरी से लेकर मार्च तक यहां मुकाबले खेले जाएंगे। रणजी मुकाबले का उद्देश्य पिच और मैदान को परखना होगा।

...आधारशिला रखी थी

रणजी मैच के सफल आयोजन के बाद यहां डब्ल्यूपीएल मुकाबले आयोजित किए जाने की संभावना है। इसके बाद स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साल 2023 में इस स्टेडियम की आधारशिला रखी थी।

कबूतर के पैर में मिला बीएएन-2024 टैग

बांग्लादेश कनेक्शन की आशंका से मयूरभंज में हड़कंप

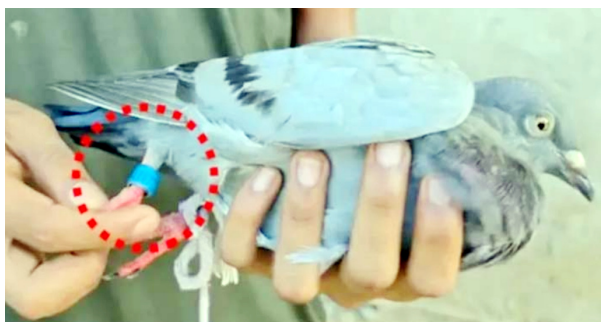

भुवनेश्वर। ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक कबूतर के पैर में विदेशी पहचान टैग मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है। बैसिंगा थाना क्षेत्र के काशीपड़ा गांव में मंगलवार को मिले कबूतर के पैर में नीले रंग की धातु की रिंग लगी थी। इस रिंग पर बीएएन-2024 और 701831 अंकित पाया गया। टैग पर लिखे बीएएन को लेकर बांग्लादेश से संबंध होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस ने अभी इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है।

जानकारी के मुताबिक, काशीपड़ा गांव के एक व्यक्ति की नजर कबूतर पर पड़ी। उसके पैर में लगी धातु की रिंग देखकर ग्रामीणों को संदेह हुआ। रिंग पर अंग्रेजी में लिखे कोड और क्रम संख्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बेतनटी के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी और बैसिंगा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कबूतर तथा टैग की जांच की।

पुलिस अधिकारियों ने रिंग पर दर्ज कोड और संख्या का विवरण जुटाना शुरू कर दिया है। शुरूआती स्तर पर यह संभावना भी जांची जा रही है कि टैग किसी कबूतर पालन, रेसिंग या प्रजनन कार्यक्रम से संबंधित पहचान चिह्न हो सकता है। हालांकि बीएएन शब्द के कारण बांग्लादेश कनेक्शन की चर्चा शुरू हुई है और पुलिस इस पहलू को भी जांच में शामिल कर रही है।

कबूतर मिलने की खबर फैलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। कुछ लोगों ने आशंका जताई कि कहीं पक्षी के माध्यम से कोई गोपनीय गतिविधि तो नहीं की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने की अपील की है।

अधिकारियों के अनुसार, कबूतर के पैर में लगा टैग किस संस्था या व्यक्ति ने लगाया, इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए टैग के कोड, क्रम संख्या और संभावित पंजीकरण से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। जरूरत पड़ने पर संबंधित विभागों और अन्य एजेंसियों से भी जानकारी साझा की जा सकती है।

स्पष्ट हो सकेगी

देश के अलग-अलग हिस्सों में पहले भी पैरों में पहचान टैग लगे कबूतर मिलने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे कई मामलों में पक्षियों का संबंध कबूतरबाजी, रेसिंग या प्रजनन गतिविधियों से पाया गया है। इसके बावजूद सुरक्षा के लिहाज से पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कबूतर कहां से आया और उसके पैर में बीएएन-2024 का टैग किस उद्देश्य से लगाया गया था। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही टैग के वास्तविक स्रोत और कबूतर के संभावित बांग्लादेश कनेक्शन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

लंदन पुलिस ने नहीं दी अनुमति, थलापति का कार्यक्रम टला

लंदन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और लोकप्रिय अभिनेता थलापति विजय के लंदन दौरे पर उनके प्रशंसकों को उस समय निराशा हाथ लगी, जब लंदन की प्रतिष्ठित इमारत द शार्ड के बाहर उनका प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। मंगलवार को बड़ी संख्या में जुटे प्रशंसक, जो अपने पसंदीदा सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नहीं दी, जिससे विजय की टीम और प्रशंसकों दोनों को झटका लगा।

पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम को हाई कोर्ट से मिली जमानत

जबलपुर। छतरपुर के चर्चित गोलीकांड में आरोपित बागेश्वर धाम के संत पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग उर्फ छोटे सरकार को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायाधीश अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाते हुए शालिग्राम को 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए।

मोतीलाल पर हमला और गोली चलाने का आरोप

मामले में आरोप है कि शालिग्राम ने

अपने साथियों के साथ मिलकर मोतीलाल कुशवाहा पर जानलेवा हमला किया था। आरोप के मुताबिक घटना के दौरान पिस्तौल से गोली भी चलाई गई। राजनगर थाना पुलिस ने मामले में शालिग्राम को 15 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जिला अदालत से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी।

बचाव पक्ष ने बताया रंजिश में फंसाने का मामला

हाई कोर्ट में शालिग्राम की ओर से अधिवक्ता रोहित रघुवंशी और अमित दवे ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने आरोपों को गलत बताते हुए राजनीतिक दबाव और पुरानी रंजिश के चलते फंसाए जाने की दलील दी।

बालोद में एनएच-30 पर बस ने बाइक सवार को 5 किमी तक घसीटा

एक पैर कट गया, शरीर बुरी तरह हुआ क्षत-विक्षत

बालोद। पुरूर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-30 पर बुधवार को सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार यात्री बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि बाइक सवार बस के साथ करीब पांच किलोमीटर तक घिसटता चला गया।

इस दौरान उसका एक पैर कट गया और शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। जानकारी के अनुसार मनीष कंपनी की यात्री स्लीपर बस जगदलपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान चारामा की ओर जा रहे बाइक सवार को सूर्यवंशी ढाबा के पास बस ने अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद बाइक सवार बस के साथ

फंस गया और बस चालक उसे करीब पांच किलोमीटर दूर स्थित टोल प्लाजा तक घसीटता ले गया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मृतक का शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया।

हादसे में जान गंवाने वाले बाइक चालक की पहचान चारामा निवासी के रूप में बताई जा रही है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुरूर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। शव को गुरुर स्थित मच्युरी में रखवाया गया है। पुलिस मृतक की पहचान सहित हादसे के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। हादसे के बाद पुरूर पुलिस ने यात्री बस के चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों, बस की रफ्तार और घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

अंडमान-निकोबार के विकास की नई दिशा पर पहले दिन से जोर

वेब वार्ता, अब्दुल साजिद

अंडमान/निकोबार। अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण करने के प्रथम दिवस पर दिनेश शर्मा ने प्रशासनिक कार्यों की शुरूआत विकास परियोजनाओं की समीक्षा के साथ की। उन्होंने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की ओर से द्वीपसमूह में संचालित और प्रस्तावित प्रमुख विकास परियोजनाओं को लेकर दिए गए विस्तृत प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया तथा विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

उपराज्यपाल के पदभार ग्रहण करने के बाद पहले ही दिन विकास योजनाओं की समीक्षा को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि द्वीपसमूह में बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सुविधाओं और विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने पर प्रशासन का विशेष ध्यान रहेगा।

बैठक के दौरान प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने द्वीपसमूह में चल रही विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं, उनकी वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। उपराज्यपाल ने

प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विकास कार्यों की समग्र स्थिति को समझा और प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर ज्ञानेश भारती, भा.प्र.से., मुख्य सचिव, रविन्द्र सिंह यादव, भा.पु.से., पुलिस महानिदेशक, संजय कुमार सिन्हा, भा.व.से., डॉ. सचिन शिंदे, भा.प्र.से., आयुक्त-सह-सचिव सहित प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से देश का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ-साथ दूरदराज के द्वीपों तक प्रशासनिक एवं नागरिक सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उपराज्यपाल के प्रथम दिवस पर हुई इस समीक्षा बैठक में प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी ने भी इसके महत्व को रेखांकित किया। बैठक में विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी सीधे प्रशासनिक नेतृत्व के समक्ष रखी गई, जिससे आने वाले समय में परियोजनाओं की निगरानी और उनके क्रियान्वयन को लेकर अधिक सक्रिय प्रशासनिक दृष्टिकोण की संभावना दिखाई देती है।

अंडमान-निकोबार में विकास की गति बढ़ाने के लिए केंद्र और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई प्रारंभिक समीक्षा बैठक को प्रशासन के आगामी कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण शुरूआत के रूप में देखा जा सकता है।

...आबादी के लिये महत्वपूर्ण है

उपराज्यपाल के रूप में दिनेश शर्मा की कार्यशैली की शुरूआत जिस तरह विकास परियोजनाओं की समीक्षा से हुई है, वह प्रशासनिक प्राथमिकताओं की दृष्टि से उल्लेखनीय है। द्वीपसमूह की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहां सड़क, संपर्क, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगार और अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन स्थानीय आबादी के लिए महत्वपूर्ण है।

दी जायेगी प्राथमिकता

पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन विकास परियोजनाओं की समीक्षा के जरिए उपराज्यपाल दिनेश शर्मा ने प्रशासनिक कार्यों की दिशा स्पष्ट कर दी है कि द्वीपसमूह के विकास से जुड़े कार्यों की प्रगति पर नियमित नजर और प्रभावी प्रशासनिक समन्वय को प्राथमिकता दी जाएगी।

संपादकीय

युद्धों से भड़कती महंगाई

अगस्त माह, 2026, में खुदरा मुद्रास्फीति 4.82 फीसदी रही, जबकि थोक मूल्य सूचकांक 9.9 फीसदी दर्ज किया गया। खाद्य महंगाई की यह स्थिति आठ माह में सर्वोच्च स्तर पर रही। भारतीय रिजर्व बैंक की तय सीमा से भी अधिक मुद्रास्फीति है। त्योहारों के मौसम में महंगाई और भी बढ़ सकती है। आम आदमी दर और प्रतिशत के इस अर्थशास्त्र को नहीं समझता। उसके लिए आटा, गेहूं, चावल, चीनी, दालें, खाद्य तेल, हरी सब्जियां, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और दूध आदि की कीमतें बढ़ती हैं, तो वह महंगाई की स्थिति है। उसकी जेब सीमित है, लिहाजा घर का बजट भी तय है। जब ये हदें टूटने लगती हैं, तो आम आदमी महंगाई से कराहने लगता है। एक वह महंगाई भी है, जो युद्ध हमें देते हैं और हम मजबूर हैं। बीते छह माह से अधिक समय से ईरान का होर्मुज जलडमरूमध्य या तो बाधित है अथवा बंद है या मिसाइल, ड्रोन के हमले जारी हैं। भारत का 50 फीसदी से अधिक कच्चा तेल, एलपीजी, खाद आदि इसी समुद्री मार्ग से आते रहे हैं। दुनिया में करीब 20 फीसदी तेल-गैस की आपूर्ति इसी मार्ग के जरिए की जाती रही है। अब लाल सागर और बाब-अल-मंदेब पर हूती लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। हालांकि उन्होंने ऐलान किया है कि वे सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाएंगे। यहां से गुजरने नहीं देंगे। भारत समेत शेष विश्व के जहाज, तेल-टैंकर आदि की आवाजाही निर्बाध रहेगी। दुनिया की करीब 12 फीसदी आपूर्ति इस जल-मार्ग के जरिए होती रही है। सऊदी अरब जिस ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के जरिए यूरोप और एशिया में कच्चे तेल का निर्यात कर रहा था, इस पर हूती लड़ाकों ने मिसाइल हमले कर उसका एक हिस्सा तबाह कर दिया है। सोमवार, 14 सितंबर, की रात तक पाइपलाइन धू-धू कर जल रही थी, लिहाजा उसे बंद करना पड़ा है। इस पेट्रोलाइन से 40-50 लाख बैरल कच्चा तेल रोजाना सप्लाई किया जाता था।

जाहिर है कि भारत सहित कई एशियाई और यूरोपीय देशों की तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। कच्चे तेल का एक और निश्चित रास्ता ठप हो गया है। चूंकि महत्वपूर्ण जल-मार्गों से आपूर्ति बाधित या ठप है, नतीजतन कच्चे तेल की कीमत भी 108 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई है। बीती 11 सितंबर को भारत के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत 119 डॉलर से अधिक थी। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के आकलन हैं कि कच्चा तेल जल्द ही 121 डॉलर प्रति बैरल को छू लेगा। यदि सभी मोर्चों पर युद्ध जारी रहे, तो कच्चा तेल 150 डॉलर तक उछल सकता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा निकल जाएगा! भारत 2.4 लाख मीट्रिक टन तेल का आयात करता है, लिहाजा उसका बिल 19 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। यह बीते साल के आयात बिल से 8 लाख करोड़ रुपए अधिक होगा। अर्थव्यवस्था पर यह अनावश्यक बोझ समझना चाहिए, नतीजतन रोजमर्रा की हरेक वस्तुएं, सेवाएं, परिवहन आदि सभी महंगे हो जाएंगे। तेल कंपनियों के घाटे का रुदन तो शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि भारत की तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 23 रुपए प्रति लीटर और एलपीजी के एक सिलेंडर पर 200 रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, ईरान में युद्धविराम (17 अगस्त, 2026) के खत्म होने के बाद 100 देशों में पेट्रोल-डीजल औसतन 5-7 फीसदी तक महंगे हो गए हैं। कच्चा तेल 17-20 फीसदी तक और एलपीजी, एलएनजी 20-25 फीसदी तक महंगी हुई हैं। भारत क्या कर सकता है? उसे 88 फीसदी कच्चा तेल आयात करना पड़ता है। अमरीका तो तेल-गैस का निर्यातक देश है, फिर भी वहां पेट्रोल-डीजल के दाम ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं कि जनता सडकों पर आंदोलित हो गई है। बहरहाल भारत के संदर्भ में यदि तेल-गैस, उर्वरक आदि के संकट घनीभूत होते रहे और महंगाई भडकती रही, तो हमारी मुद्रा रुपए का अवमूल्यन भी चिंता के स्तर पर पहुंच सकता है। आश्चर्य है कि भारत सरकार मुद्रास्फीति और ऊर्जा-संकट पर बिल्कुल मौन है, मानो आम भारतीय ह्यमौजह्न में है! जीडीपी की विकास दर पर देश को भ्रमित भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस विकास में मुद्रास्फीति भी निहित है। यदि उसे घटा दिया जाए, तो विकास दर 2.5 फीसदी के आसपास होगी। क्या यही हमारा यथार्थ है? महंगाई के कारण गरीबों का जीना कठिन हो रहा है। इससे मध्यम वर्ग भी प्रभावित हो रहा है। सरकार का कहना है कि उसने कई करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। यानी गरीबी अब कम हो गई है। लेकिन धरातल पर यह सत्य भी है कि कई करोड़ लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध करवा कर उनका पोषण किया जा रहा है। इसे हम विकास नहीं मान सकते। विकास के लिए समूह नागरिकों का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। जब कई करोड़ हाथ कमाने लग जाएंगे, तो ही वास्तव में विकास दिखेगा। केवल भोजन की कमी को दूर कर देने और सस्ता राशन बांट कर गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकला जा सकता।

प्रमाणपत्रों का चक्रव्यूह व नागरिक उत्पीड़न

वर्तमान समय में जब डिजिटल क्रांति के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, तब एक आम करदाता नागरिक का केवल एक अक्षर या जन्मतिथि की त्रुटि सुधारने के लिए महीनों तक कार्यालयों के चक्कर काटना प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है।

हालांकि यह राष्ट्रीयता के हित में है कि भारत के प्रत्येक नागरिक की नागरिकता के संबंध में विभिन्न प्रकार के पहचानपत्र बनाए जा रहे हैं, फिर भी आधार, मतदाता, विवाह, जन्म, मृत्यु, स्थायी निवास, मूल निवास, पासपोर्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक योजनाओं से संबंधित अनेक पहचानपत्रों को बनाने के लिए देशभर में जितने भी संबंधित संस्थान हैं, वे पहचान-पत्रों की हर स्तर पर एकरूपता बनाए रखने के लिए परस्पर समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। केंद्रीय शासन एवं प्रादेशिक शासन के अंतर्गत जन सेवा केंद्र तो अवश्य खोले गए हैं, जहां आरंभ में तो सभी प्रकार के पहचान-पत्र बन जाते थे, किंतु अब ये केंद्र भी किसी भी पहचान को पूरी तरह अपने स्तर पर प्रमाणित एवं प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। अब इन्हें केवल पहचान हेतु प्रस्तावित नाम से लेकर उसके अन्य विवरणों को अद्यतन करके ऑनलाइन अपलोड करने के कार्यदायित्व तक ही सीमित कर दिया गया है। जब से शासन के निदेर्शानुसार आधार प्राधिकरण ने आधार पहचान-पत्र को नागरिकों के बैंक खातों एवं खातों में सूचीबद्ध मोबाइल नंबर से जोड़ा है, तब से आधार पत्र, मोबाइल नंबर एवं बैंक खातों में होने वाली किसी भी अनियमितता एवं त्रुटि के लिए केवल और केवल नागरिकों को दोषी ठहराकर, त्रुटि निवारण हेतु उनसे तरह-तरह के प्रमाणपत्र मांगे जा रहे हैं। चाहे किसी भी पहचान-पत्र में त्रुटियां संबंधित संस्थान अथवा प्राधिकरण के कारण हुई हों, किंतु त्रुटियों को ठीक करने के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्र, पहचान-पत्र धारक नागरिक को ही उपलब्ध कराने पड़ रहे हैं।

इस क्रम में सामान्य नागरिकों को, और विशेषकर देश के मूल नागरिकों को, अत्यंत कष्ट एवं मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कष्ट व मानसिक उत्पीड़न पहचान-पत्र बनाने वाले किसी संस्थान अथवा उसके कर्मचारी के कारण नहीं, अपितु पहचान सिद्ध करने के लिए जटिल कर दी गई शासकीय कार्यप्रणालियों के कारण हो रहा है। देश में परिव्याप्त कई तरह की समस्याओं के स्थायी उन्मूलन के लिए यदि देश के करोड़ों लोगों के प्रामाणिक प्रमाणपत्र बनाने की अनिवार्यता उभरी है, तो इसके लिए एक व्यापक कार्यनीति की आवश्यकता थी। केंद्रीय शासन को इस हेतु अपने अधीन एक नागरिक प्रलेख एवं प्रमाणन विभाग खोलकर देश के प्रत्येक जनपद में इसके चार-चार कार्यालय खोलने चाहिए थे। राज्यों के भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय आकार को देखकर जनपद स्तर पर चार से अधिक कार्यालय भी खोले जा सकते हैं। इस हेतु शासकीय स्तर पर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति हो। इस प्रयास से शासन के स्तर पर एक नवीन शासकीय विभाग गठित हो सकेगा तथा साथ ही साथ शासकीय नियुक्तियां भी हो सकेंगी। यह देश में बेरोजगारी कम होने की दिशा में एक प्रेरक चरण होगा। इन विभागों के कर्मचारी देशभर में प्रत्येक नागरिक के घर जाकर पूर्व-निर्धारित समुचित शुल्क के भुगतान पर उनका हर प्रकार का पहचान, परिचय एवं नागरिकता पत्र बनाएं। पत्र बनाने के लिए निर्धारित शर्तों में से अधिसंख्य अथवा किसी शर्त की पूर्ति न होने पर नागरिक को शर्त/शर्तें पूरा करने का अवसर दिया जाए। पत्र हेतु आवश्यक जानकारियों, सूचनाओं एवं विवरणों को विभागीय कर्मचारियों व पदाधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए। यदि नागरिक भारत का मूल निवासी है तथा उसके पास किन्हीं कारणों से अपनी भारतीय नागरिकता सिद्ध करने हेतु कोई प्रमाण अथवा पत्र नहीं है, तो विभागीय पदाधिकारियों के पास न्याय एवं पहचान के प्राकृतिक व सामाजिक सिद्धांत के आधार पर उसे भारतीय मूल नागरिक मानने तथा इस संबंध में उसे प्रमाणपत्र देने का अधिकार होना चाहिए।

यदि शासन का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक की नागरिकता प्रमाणित कर देश में विद्यमान अवैध लोगों की पहचान उजागर करना है अथवा शासन चाहता है कि वह सज्जन नागरिकों के बीच में से दुर्जन एवं देशविरोधी नागरिकों की पहचान करके उन्हें कठोर दंड दे, तो ऐसा करे। किंतु ऐसा हो कहां रहा है! ऐसा होने की राह में अनेक विसंगतियां परिव्याप्त हैं। इसी कारणवश अपनी-अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए देश के करदाताओं, सज्जन एवं मूल नागरिकों को अधिक परिश्रम करना पड़ रहा है। इसमें उनका समय एवं धन, दोनों का व्यय हो रहा है। साथ ही साथ मूल नागरिक होकर भी तथा करदाता की भूमिका में होते हुए भी उन्हें अपनी नागरिकता की मौलिक पहचान सिद्ध करने के लिए भीषण संघर्ष करना पड़ रहा है। स्थान-स्थान पर लंबी-लंबी पंक्तियों में प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। मौलिकता की प्रलेखीय पहचान सिद्ध होने तक उन्हें कितने अधिक मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ रहा है। प्रलेखीय स्तर पर मौलिकता सिद्ध होने तक मूल नागरिक होकर भी वे स्वयं को देश में पराया मान रहे हैं। क्या किसी मूल नागरिक के लिए आम साधारण व्यक्ति होकर यह कम मानसिक आघात है? यह अत्यंत कष्टकारी अनुभव है। इसका अनुभव वही कर सकता है, जो पारिवारिक साधारण व्यक्ति है तथा भारत का मूल नागरिक होकर भी स्थान-स्थान पर विभिन्न विभागों में जा-जा कर अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए प्रमाणपत्रों के चक्रव्यूह में पिस रहा है। यहां ऊपर पहले ही लिखा जा चुका है कि देश के सज्जन, सत्यनिष्ठ, करदाता एवं पीढ़ियों से मूल नागरिक होने का अधिकार रखने वाले व्यक्तियों के हर प्रकार के शासकीय पहचान एवं परिचय पत्र उनके घर अथवा कार्यालय में जाकर बनवाए जाएं। इस हेतु केंद्रीय शासन को एक विस्तृत कार्ययोजना बनानी होगी। एक नवीन नागरिक प्रलेख एवं प्रमाणन विभाग खोलना होगा, जो केंद्रीय स्तर का विभाग होगा, जिसकी अधिक से अधिक शाखाएं देश के सभी जनपदों में गठित की जाएं। केंद्रीय विभाग एवं इसकी जनपद स्तर की शाखाओं में अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति हो। वे सरकारी कर्मचारी हों। उन्हें समस्त सरकारी सुविधाएं, लाभ एवं अन्य सहायताएं प्राप्त हों। नागरिक प्रलेख एवं प्रमाणन विभाग देश में पहले से कार्यरत चुनाव आयोग, आधार प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित पहचान निर्धारण संस्थानों के साथ कार्यकारी समन्वय स्थापित करके देश के प्रत्येक नागरिक के समस्त पहचानपत्रों, परिचय-पत्रों तथा अन्य पत्रों को बनाने, बनाते समय उनमें हुई त्रुटियों को ठीक करने, विवरणों को संशोधित करने तथा अंततः पत्रों को नागरिक तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य करे।

इस एकीकृत और जन-हितैषी व्यवस्था के लागू होने से न केवल आम जनता को पहचान-पत्रों की त्रुटि-सुधार प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी, बल्कि शासकीय प्रणालियों की विश्वसनीयता में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी। वर्तमान समय में जब डिजिटल क्रांति के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, तब एक आम करदाता नागरिक का केवल एक अक्षर या जन्मतिथि की त्रुटि सुधारने के लिए महीनों तक कार्यालयों के चक्कर काटना प्रशासनिक विफलता को दशार्ता है। सरकार का प्राथमिक दायित्व नागरिक को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है, न कि उसे अपनी ही पहचान सिद्ध करने के लिए संदिग्ध की भांति खड़ा कर देना। यदि यह प्रस्तावित नागरिक प्रलेख एवं प्रमाणन विभाग पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है, तो देश में डिजिटल इंडिया की अवधारणा वास्तव में सार्थकता प्राप्त करेगी। इससे डेटा की पुनरावृत्ति रुकेगी, जिससे राजस्व और संसाधनों की भारी बचत होगी।

विकेश कुमार बडोला, स्वतंत्र स्तंभकार

रियल एस्टेट पर मंदी की दस्तक, मकान हैं, खरीदार गायब

भारत का रियल एस्टेट बाजार ऐसे दौर में पहुंच रहा है, जहां मांग, कीमत और आपूर्ति के बीच असंतुलन बढ़ता चला जा रहा है। जो आने वाले महीनों में एक बड़ी चुनौती बन सकता है। 2026 की दूसरी तिमाही में देश के सात प्रमुख शहरों में आवासीय बिक्री घटकर 90,715 इकाई रह गई। यह पिछली तिमाही से 11 फीसदी और एक साल पहले की समान अवधि से 6 फीसदी कम है। 2023 की शुरूआत के बाद का इसे सबसे कमजोर तिमाही प्रदर्शन बताया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल बिक्री करीब 4.04 लाख इकाई की रही, जो वित्त वर्ष 2022-23 के बाद से सबसे कम है। जिसके कारण अब रियल स्टेट को लेकर एक नई चिंता पैदा हो गई है। दूसरी तरफ तैयार और निमार्णाधीन मकानों का स्टॉक बढ़ता जा रहा है। शीर्ष सात शहरों में उपलब्ध आवासीय भवन और फ्लैट 2026 की दूसरी तिमाही के अंत तक करीब 10 फीसदी बढ़कर 6.16 लाख से अधिक इकाई हो गई है। समस्या केवल यह नहीं है, लोग मकान नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि बिल्डरों ने जिस गति से नई परियोजनाएं शुरू की हैं, उस अनुपात में बिक्री नहीं हो रही है। बेंगलुरु इसका बड़ा उदाहरण है। 2026 की पहली तिमाही में वहां 26,297 नई आवास योजना इकाइयां लॉन्च हुईं, बिक्री केवल 16,745 इकाइयों की हुई। परिणामस्वरूप पूर्व और वर्तमान के बिना बिके आवासों की संख्या करीब 87,796 इकाइयों तक पहुंच गई है। हैदराबाद में भी पहली छमाही में बिक्री 13 फीसदी घटकर 26,068 इकाई रह गई है। बिना बिके मकानों का आंकड़ा 1.4 लाख से अधिक हो गया है। यह स्थिति इसलिए गंभीर है, रियल एस्टेट केवल बिल्डरों का कारोबार नहीं है, इसके पीछे बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, एनबीएफसी, निवेशक, ठेकेदार और करोडों लोग इस रोजगार से जुड़े हैं। परियोजनाओं के लिए लिया गया कर्ज तब दबाव बन जाता है, जब बिक्री की रफ्तार धीमी हो। ऐसी स्थिति में बिल्डरों के ऊपर ब्याज लगातार बढ़ता जाता है। आवास की लागत बढ़ जाती है। मार्केट में डिमांड नहीं होने से कम मूल्य पर भी आवास नहीं बिक रहे हैं। बिल्डर वित्तीय संस्थानों और जिन लोगों ने आवास लेने के लिए ऋण लेकर पैसा निवेश किया है। सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। हालिया जानकारी के अनुसार प्रमुख डेवलपर्स पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में 21बड़ी कंपनियों में केवल तीन के पास परियोजना में खर्च करने के लिए पूंजी थी। बाकी बिल्डरों के पास परियोजना पूरी करने के लिए पैसा नहीं था। बैंकिंग क्षेत्र मे इस स्थिति को लेकर चिंता देखने को मिल रही है। आरबीआई के जून 2026 वित्तीय स्थिरता आकलन के अनुसार मार्च 2026 में बैंकों का सकल एनपपीए अनुपात 1.8 प्रतिशत था। सामान्य परिस्थितियों में बैंकों का मानना है, मार्च 2028 तक इसका 1.9 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन जिस तरह की स्थिति तेजी के साथ बन रही है, उसके अनुसार आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है, आर्थिक दबाव की स्थिति में यह अनुपात 3.8 से 4.1 फीसदी तक पहुंच सकता है।

यही सबसे बड़ा खतरा है। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, कॉरपोरेट कंपनियां छटनी कर रही हैं। यदि वह अपना मकान अथवा फ्लैट बेचना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें वह कीमत भी नहीं मिल पा रही है, जो उन्हें बैंक में चुकाना है। जिसके कारण अब लोगों का रियल एस्टेट से जो भरोसा था हमेशा कीमतें बढ़ेगी। लोन चुकाने के लिए यदि वह अपने फ्लैट या मकान को बेचेंगे तो उन्हें अलग से कोई आर्थिक इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। पिछले वर्षों में इसी कारण रियल स्टेट की मांग घटती चली जा रही है। मकानों की बिक्री लंबे समय तक कमजोर रहती है, तो बिल्डरों का नकदी प्रवाह, प्रभावित होगा। कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं रहेगी। यह दबाव बैंकिंग क्षेत्र तक पहुंचने लगा है। इसलिए सरकार और आरबीआई को नई परियोजनाओं को ऋण देने के स्थान पर जो संपत्तियां अभी नहीं बिकी हैं, उन पर प्रोत्साहन देने की जरूरत है। डेवलपर के कर्ज, वास्तविक आवासीय मांग, पर भी नजर रखनी होगी।

चीन के रियल सेक्टर में भारी मंदी देखने को मिल रही है। यहां पर 20 से लेकर 40 फीसदी तक की गिरावट है। मकान के लिए लोगों ने भारी कर्ज लिया था, लेकिन वह अपने वेतन से कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। अचानक नौकरियां जा रही हैं, जिसके कारण उन्हें मकान बेचना पड़ता है। जितने में उन्होंने मकान खरीदा था, उससे आधी कीमत भी नहीं मिल पा रही है। इस स्थिति के कारण अब आवास के लिए कर्ज लेने वालों की संख्या तेजी के साथ घट रही है। वहीं निवेश करने वालों ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं। संपत्ति का जितना मूल्य है उसके हिसाब से किराया बहुत कम मिल रहा है। पिछले दो दशक में रियल स्टेट का जो बूम आया था, अब वह मंदी की चपेट में आ गया है। रियल एस्टेट में असली सुधार तभी माना जाएगा, जब आवास की कीमतें आम लोगों की आय के अनुरूप हों। नौकरी जाने पर वह अपना मकान होल्ड कर सकें। रियल एस्टेट की परियोजनाओं में बिक्री और आपूर्ति में संतुलन बने। तैयार मकानों की बिक्री हो, ताकि उनमें रख-रखाव का खर्च खत्म हो। चमकदार टावरों और मीडिया के विज्ञापनों के पीछे खड़ी लाखों खाली संपत्तियां भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी वित्तीय चुनौती बन गई है। भारत को चीन और दुनिया के अन्य देशों से सबक लेने की जरूरत है। जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद रियल स्टेट का कारोबार बढ़ेगा, यह केवल कपोल कल्पना है। भारत का रियल एस्टेट और भारत की आर्थिक स्थिति में जो गिरावट देखने को मिल रही है, वह पूरी अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा खतरे के रूप में देखने को मिलेगी। इसको लेकर भारत के आर्थिक विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। इसका बड़ा व्यापक असर सभी सेक्टर में पड़ने की संभावना है।

(लेखक- सनत जैन)

लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा फेक न्यूज

जब हम किसी सनसनीखेज वीडियो को सत्यापित किए बिना साझा करते हैं, तो हम उसके प्रभाव के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और जब हम किसी अफवाह को रोकने के बजाय उसे आगे बढ़ाते हैं, तो हम अनजाने में सामाजिक विश्वास को कमजोर करते हैं। लोकतंत्र केवल सत्ता बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह विश्वास पर टिका हुआ एक सामाजिक अनुबंध है।

इसमें नागरिकों का संस्थाओं पर विश्वास, संस्थाओं का नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व और समाज के भीतर संवाद की ऐसी संस्कृति का निर्माण शामिल है, जिसमें असहमति के बावजूद एक-दूसरे को सुनने की क्षमता और दूसरों के मतों को तवज्जो देने की भावना बनी रहती है। लेकिन आज इस विश्वास की नींव को एक अदृश्य चुनौती लगातार कमजोर कर रही है जैसे गलत, भ्रामक और अपुष्ट सूचना का तेजी से फैलता जाल। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने निर्णय प्रक्रिया को समृद्ध बनाने, विश्वास बढ़ाने तथा अधिक शांतिपूर्ण, समावेशी और लचीले समाजों के निर्माण के लिए समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनके संदेश में लोकतंत्र को केवल एक संस्थागत व्यवस्था नहीं, बल्कि लोगों की भागीदारी और विश्वास से मजबूत होने वाली व्यवस्था के रूप में रेखांकित किया गया है। लेकिन आज सवाल यह है कि जब समाज के अलग-अलग वर्गों तक अलग-अलग सच पहुंच रहा हो, तब उन्हें एक साथ कैसे लाया जाए? आज सूचना हमारे हाथ में है, लेकिन सत्य की पहचान पहले से अधिक कठिन होती जा रही है। एक मोबाइल फोन कुछ ही सेकंड में हमें देश-दुनिया की खबरों से जोड़ देता है। व्हॉट्सऐप, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया मंचों ने सूचना के लोकतंत्रीकरण को गति दी है। मगर इसी के साथ मिसइन्फॉर्मेशन यानी भ्रामक जानकारी, डिसइन्फॉर्मेशन यानी जानबूझकर फैलाई गई गलत सूचना और डीपफेक जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। समस्या केवल यह नहीं है कि कोई व्यक्ति गलत सूचना फैला रहा है।

असली संकट तब पैदा होता है, जब गलत सूचना सही लगने लगे और सही सूचना पर ही संदेह होने लगे। यही लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। हर वर्ष 15 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल लोकतांत्रिक अधिकारों की याद नहीं दिलाता, बल्कि हमें हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। लोकतंत्र की रक्षा संसद में होने वाली बहसों से जितनी होती है, उतनी ही हमारे मोबाइल फोन पर आने वाले एक संदेश के साथ हमारे व्यवहार से भी होती है। एक खबर को सत्यापित करने में लगे दो मिनट लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान दे सकते हैं। यूनेस्को ने 2026 में प्रेस स्वतंत्रता और सूचना के वातावरण पर चिंता जताते हुए बताया कि सूचनाओं में हेरफेर सार्वजनिक विश्वास को कमजोर कर रहा है। संस्था ने मीडिया और सूचना साक्षरता को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। लेकिन सोचिए, एक समाज में यदि नागरिकों को यह भरोसा ही न रहे कि उन्हें मिलने वाली खबर सच है, तो वे अपने निर्णय किस आधार पर लेंगे? चुनाव में किस आधार पर राय बनाएंगे? किसी सार्वजनिक नीति का समर्थन या विरोध किस आधार पर करेंगे? किसी सामाजिक घटना पर प्रतिक्रिया देने से पहले किस पर विश्वास करेंगे? लोकतंत्र में नागरिक का मत तभी सार्थक है, जब उसका निर्णय विश्वसनीय सूचना पर आधारित हो। इसलिए गलत सूचना केवल सूचना के माध्यम की समस्या नहीं है, बल्कि अब यह लोकतंत्र की समस्या बन चुकी है। एक झूठी खबर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। एक भ्रामक स्वास्थ्य संदेश किसी व्यक्ति को इलाज से दूर कर सकता है। किसी समुदाय के बारे में गलत सूचना सामाजिक तनाव पैदा कर सकती है। चुनाव के समय फैलाया गया दुष्प्रचार मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए नकली वीडियो किसी व्यक्ति के शब्द और चेहरा तो दिखा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें दिखाई गई बात कभी कही या हुई भी हो। सबसे दुखद बात यह है कि हम अक्सर वही सूचना स्वीकार करने लगते हैं, जो हमारे पहले से बने विचारों की पुष्टि करती है। यहीं से ह्यइको चैंबरह्न बनते हैं। हम उन्हीं लोगों को सुनते हैं, जो हमसे सहमत हैं। उन्हीं पोस्ट को पसंद करते हैं, जो हमारी सोच को सही ठहराती हैं। धीरे-धीरे असहमति रखने वाला व्यक्ति हमें विरोधी नहीं, बल्कि दुश्मन दिखाई देने लगता है। लोकतंत्र का स्वभाव इसके ठीक विपरीत है। लोकतंत्र हमें यह अधिकार देता है कि हम असहमत हो सकें। लेकिन असहमति को दुश्मनी बनने से रोकने के लिए आवश्यक है कि समाज में संवाद की एक साझा जमीन तैयार की जाए। यही साझा जमीन विश्वसनीय तथ्यों से बनती है। इसलिए आज मीडिया की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। पत्रकारिता का मूल्य सबसे पहले उसकी विश्वसनीयता में है। खबर सबसे पहले देने की होड़ में यदि सत्य पीछे छूट जाए, तो पत्रकारिता अपनी मूल भूमिका खो देती है। सनसनी पाठक को आकर्षित कर सकती है, लेकिन विश्वास केवल सत्य से बनता है। मीडिया संस्थानों को तथ्य जांच, स्रोतों की पुष्टि, पारदर्शिता और नैतिक पत्रकारिता को प्राथमिकता देनी होगी। सोशल मीडिया मंचों को भी अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए। लेकिन सारी जिम्मेदारी मीडिया या तकनीकी कंपनियों पर डालकर नागरिक अपनी भूमिका से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि एक नागरिक भी सूचना-व्यवस्था का हिस्सा है। जब हम बिना पढ़े कोई संदेश आगे भेजते हैं, तो हम केवल एक संदेश नहीं भेज रहे होते, बल्कि उसके साथ जुड़ी संभावित गलत सूचना को भी आगे बढ़ा रहे होते हैं। जब हम किसी सनसनीखेज वीडियो को सत्यापित किए बिना साझा करते हैं, तो हम उसके प्रभाव के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और जब हम किसी अफवाह को रोकने के बजाय उसे आगे बढ़ाते हैं, तो हम अनजाने में सामाजिक विश्वास को कमजोर करते हैं। इसलिए आज के नागरिक को केवल शिक्षित होना पर्याप्त नहीं है। उसके साथ-साथ मीडिया साक्षर होना भी जरूरी है। हमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक यह समझाना होगा कि किसी सूचना को देखने के बाद पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए कि ह्यइसे कितने लोगों ने शेयर किया?ह्न, बल्कि यह होना चाहिए कि इसका स्रोत क्या है? क्या यह खबर किसी विश्वसनीय संस्था ने प्रकाशित की है?

डा. निधि शर्मा, शिक्षाविद

आलेख

ब्रह्माकुमारीज के मानसरोवर में संस्कारों की डुबकी लगाई पत्रकारों ने!

खबरों के लिए भागदौड़ भरी की जिंदगी के बीच तनावमुक्त जीवन जीने और मेडिटेशन के टिप्स सीखने के लिए देशभर से 2000 से अधिक मीडियाकर्मियों ने आबूरोड राजस्थान के ब्रह्माकुमारीज संस्थान मान सरोवर 5 दिनों तक संस्कारों की डुबकी लगाई। मीडिया व पीआर विंग द्वारा आयोजित पांच दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन में प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, रेडियो, बेव, सोशल मीडिया से जुड़े संवाददाता, संपादक और जनसंपर्क से जुड़े पत्रकारो ने भाग लिया। इस दौरान सभी मीडियाकर्मियों ने हाथ उठाकर नशामुक्ति का संकल्प भी लिया।महासम्मेलन में 7-सूत्रीय कार्य योजना को अपनाया गया। ह्नबेहतर विश्व के निर्माण के लिए सशक्त मीडियाह्न विषय पर आधारित इस महासम्मेलन में मीडिया उद्योग को सतही सामाजिक संघर्षों से आगे बढ़कर व्यावहारिक समाधानों को प्रसारित करने के लिए अपने मंचों को समर्पित करने की चुनौती दी गई। विंग की उपाध्यक्ष बी.के. सरला द्वारा प्रस्तुत व प्रो. मानसिंह परमार तथा प्रो. संजय द्विवेदी द्वारा समर्थित प्रस्ताव में पत्रकारिता की सत्यनिष्ठा को बहाल करने के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा तैयार की गई है। इस नव-पारित कार्य योजना का एक मुख्य जनादेश विभिन्न प्रकार के मीडिया माध्यमों में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय मीडिया परिषद की स्थापना करने की औपचारिक मांग करना है।

इस योजना में वैश्विक डिजिटल नकारात्मकता की बढ़ती लहर से निपटने के लिए गहन मीडिया साक्षरता में तेजी से वृद्धि करने की मांग की गई है, जिसका उद्देश्य निष्क्रिय उपभोक्ताओं को जिम्मेदार डिजिटल नागरिकों में बदलना है। प्रस्ताव दस्तावेज में दृढ़ता से कहा गया है कि रचनाकारों के आंतरिक आध्यात्मिक सशक्तिकरण के बिना मीडिया नैतिकता को ऊपर उठाने के लिए संरचनात्मक नियम और तकनीकी तथ्य-जांच उपकरण अंततः नाकाफी हैं। प्रस्ताव में मीडिया संगठनों और सहयोगी जनसंपर्क नेटवर्क को शांति, समानता, स्थिरता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने वाले लक्षित अभियानों को शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध करने की बात कही गई है।

वही वर्तमान मीडिया परिवेश के तीव्र मानसिक और सामाजिक नुकसान को रेखांकित करते हुए, एएएफटी, नोएडा फिल्म सिटी के डीन डॉ. विकास सिंह ने एक तनावग्रस्त मीडिया पेशेवर का एक मार्मिक उदाहरण साझा किया, जिसे अपनी बेटी को एक मनोचिकित्सक के पास ले जाना पड़ा क्योंकि वह अपने पिता से ही डरने लगी थी। डॉ. सिंह ने उपस्थित पत्रकारों से आग्रह किया कि वे पूरे समाज को अपने बच्चों की तरह देखें और अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से शांति के लिए सक्रिय रूप से काम करें। प्रसार भारती न्यूज सर्विस, नई दिल्ली के वरिष्ठ संपादक (डिजिटल) उमानाथ सिंह ने स्वीकार किया कि वैश्विक युद्धों के प्रभुत्व वाले इस दौर में शांति के बारे में सोचना बेहद कठिन है, लेकिन उन्होंने प्रेस के भीतर आवश्यक आध्यात्मिक लचीलापन जगाने के संगठनात्मक प्रयासों की सराहना की। मतभेदों को पाटने की मीडिया की शक्ति पर जोर देते हुए, नेपाल के ह्यकल्याणपोस्ट की संपादक व विधायक माला कुमारी कर्ण ने कहा कि पत्रकारिता को लोगों के आपसी संबंधों को सुरक्षित रखना चाहिए जो सीमाओं से परे हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों को याद दिलाया कि कलम आज भी तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है।अपना आशीर्वाद देते हुए, ब्रह्माकुमारीज की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी.के. मोहिनी दीदी ने मीडिया प्रतिनिधियों को एक आध्यात्मिक ढांचा प्रदान किया, जिसमें उन्होंने एक भाग्यशाली जीवन के चार स्तंभों को रेखांकित किया: विचार शक्ति पर नियंत्रण रखना, आधुनिक चिंताओं के बावजूद शांति के शारीरिक स्पंदन बनाए रखना, धन का सही उपयोग करना और हर किसी को एक आत्मा के रूप में देखकर सार्वभौमिक मित्रता की भावना विकसित करना शामिल है।उन्होंने समाचार कक्ष (न्यूजरूम) के अत्यधिक दबाव को स्वीकार करते हुए, पत्रकारों को दुनिया की नकारात्मकता से अछूते रहने की सलाह दी और एक आदर्श रिपोर्टर की तुलना कमल के फूल से की, जो कीचड़ से घिरे होने पर भी चमकता रहता है।

भोपाल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संजीव गुप्ता ने कहा कि चूंकि मीडिया ह्नमन के लिए भोजनह्न परोसता है, इसलिए पत्रकारों को सच्ची शांति और खुशी को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिकता की नितांत आवश्यकता है। मीडिया महासम्मेलन में 14 विशेष सत्र शामिल किए गए—जिनमें प्लेनरीज, इनसाइट टॉक्स औरमेडिटेशन शामिल ।जिनके माध्यम से पेशेवर मीडिया नैतिकता को आंतरिक स्थिरता के साथ जोड़ने के लिए तैयार किया गया ।श्रेष्ठ विश्व के निर्माण हेतु सशक्त मीडिया विषय पर आयोजित इस मीडिया महासम्मेलन के शुभारंभ पर वरिष्ठ पत्रकार सरफराज सैफी ने कहा कि क्या मीडिया सिर्फ खबर दिखाएगा यहा खबर के पीछे की सच्चाई भी सबके सामने लाएगा? क्या मीडिया वाले सिर्फ शोर करेंगे या समाज को सही दिशा दिखाने का मौका हमें मिलेगा या मिल रहा है? यह सवाल स्वयं से पूछने की जरूरत है।

सैफी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कंटेंट समाज को दे रहे हैं उससे समाज को नई दिशा मिले और श्रेष्ठ समाज के निर्माण में सहायक हो। ब्रह्माकुमारीज ऐसे आयोजनों के माध्यम से पत्रकारों को मूल्यनिष्ठ जीवन जीने की कला सिखा रही है। पत्रकारों को भीतर से सुकून की जरूरत है, जब हमारे भीतर सुकून होगा तो समाज को बेहतर तरीके से आइना दिखा पाएंगे। हमें अंदर से ब्रांडेड बनने की जरूरत है। हम पत्रकारों को बहुत सकारात्मक होने की जरूरत है। वरिष्ठ पत्रकार यशवंत राणा ने कहा कि मानव सभ्यता के इतिहास में जिस खतरनाक मोड़ पर हम खड़े हैं, इसके पहले यह कभी नहीं हुआ। एआई ने मानव के लिए कई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं।

ब्रह्माकुमारीज मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा भाई ने कहा कि भारत जल्द ही विश्व गुरु बनेगा। हम इसी स्वप्न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विश्व के हालात आज हम सभी के सामने हैं। समय को देखते हुए यदि विश्व को कोई नई राह दिखा सकता है तो वह है भारत। जब तक मीडिया क्रांति के रूप में नहीं लेगा, हमारा स्वप्न साकार नहीं होगा। प्रो. संजय द्विवेदी ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज के इन माउंट आबू के परिसरों में आध्यात्मिकता की आबोहवा बहती है। यह जगह अध्यात्म और शौर्य, साहत से ओतप्रोत है। पूर्व कुलपति प्रो. मान सिंह परमार ने कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व को जोड़ने की रही है। श्रेष्ठ विश्व के निर्माण में हम सहयोगी बन सकते हैं ।उन्होंने कहा कि हमें सूचना और समाचारों में अंतर समझना जरूरी है। हमारा समाचार ऐसा हो जो समाज को जोड़ने का काम करे। राजयोगिनी बीके सुषमा दीदी ने कहा कि समय आ गया है कि अब विश्व परिवर्तन होने वाला है, इस सत्य को मानना ही होगा। इस धरा पर ही एक ऐसे विश्व की रचना होगी, जहां देवी-देवताओं का राज्य होगा। आत्मिक स्वरूप को जागृत करने की कला और शक्ति का आधार उन्होंने राजयोग को बताया। विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके निकुंज भाई ने कहा कि आप सभी यहां से कुछ नया सीखकर जाएं। कुछ लेकर जाएं ताकि अपने सेवा स्थान पर जाकर कुछ नवीनता जरूर लाएं। जयपुर की बहन चन्द्रकला के संचालन में मीडिया महासम्मेलन के दौरान निकुंज भाई की अंग्रेजी भाषा मे लिखी पुस्तक व श्रीगोपाल नारसन की वरदान है उपभोक्ता कानून का विमोचन किया गया।इस महासम्मेलन में रायपुर छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी,चंडीगढ़ से बीके पूनम व पत्रकार केवल तिवारी,विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के उपकुलपति डॉ श्रीगोपाल नारसन, उत्तराखंड से सूचना उपनिदेशक मनोज श्रीवास्तव, फिल्म निर्देशक डॉ सुभाष अग्रवाल,देवभूमि पत्रकार यूनियन के प्रदेश महामंत्री वीडी शर्मा, विधि संवाददाता लक्ष्मण सिंह आदि की सहभागिता रही।

लेखक - डॉ. श्रीगोपाल नारसन

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

आईआईटी दिल्ली में बनी जांच समिति का समय बढ़ा

नई दिल्ली, 16 सितंबर (वेब वार्ता)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली ने 31 वर्षीय एमएससी छात्र की आत्महत्या से मौत की परिस्थितियों की जांच कर रही पांच सदस्यीय समिति का कार्यकाल दो सप्ताह बढ़ा दिया है। अब समिति को अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट 30 सितंबर तक सौंपनी होगी। समिति की अध्यक्षता दिल्ली हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता कर रही हैं।

आईआईटी दिल्ली के रजिस्ट्रार अतुल व्यास की ओर से 14 सितंबर को छात्रों और शिक्षकों को भेजे गए आंतरिक ईमेल में कहा गया कि समिति के अनुरोध पर निदेशक ने जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए बाहरी जांच समिति का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। ज्ञात हो कि 22 अगस्त को आईआईटी दिल्ली के एमएससी भौतिकी के एक छात्र की लेक्चर हॉल परिसर की छठी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। संस्थान ने इसे आत्महत्या बताया था। घटना के बाद परिसर में करीब एक सप्ताह तक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था।

अखबार में पढ़ी हर बात पीआईएल का आधार नहीं हो सकती: हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 16 सितंबर (वेब वार्ता)। नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के आरोप और दिल्ली पुलिस के इससे इनकार के मामले में हाईकोर्ट ने दायर जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने मीडिया में आई विरोधाभासी खबरों के आधार पर पुलिस से मामले की सच्चाई सामने लाने और जवाबदेही तय करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका का अधिकार क्षेत्र इस तरह के मामलों के लिए नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्हें अपनी शिकायत पर दिल्ली पुलिस से फैसला कराने का कोई वैधानिक अधिकार किस कानून के तहत मिला है। पीठ ने टिप्पणी की कि अखबार में पढ़ी हर बात के आधार पर जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को यह बताना होगा कि किसी कानूनी या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है या किसी अधिकार से इनकार किया गया है। केवल जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे शब्दों के आधार पर पीआईएल दाखिल नहीं की जा सकती। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार किया है, जबकि मीडिया में इसके विपरीत खबरें सामने आई हैं।

डीडीए ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए शुरू किया सर्वे

नई दिल्ली, 16 सितंबर (वेब वार्ता)। इंदिरा कल्याण विहार में डीडीए की टीमें कर रहीं सर्वे नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राजधानी की झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास से जुड़ा सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया है। इस सर्वे के तहत झुग्गियों में रहने वाले निवासियों की संख्या और उनकी पात्रता से जुड़े दस्तावेजों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। शुरूआत ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 साइट-2 स्थित जेजे क्लस्टर इंदिरा कल्याण विहारबसे की गई है। जहां डीडीए की इन-सीटू स्लम पुनर्वास शाखा की टीम सर्वेक्षण कार्य में जुटी है।

डीडीए की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में झुग्गी निवासियों से अनुरोध किया गया है कि वे सर्वेक्षण के दौरान उपस्थित रहकर आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराएं व सर्वे टीम को पूरा सहयोग दें, ताकि यह कार्य सुचारु रूप से पूरा हो सके। अधिकारियों के अनुसार इस तरह का सर्वेक्षण चरणबद्ध तरीके से राजधानी की अन्य झुग्गी बस्तियों में भी किया जाएगा।

यमुना में मूर्ति विसर्जन पर रोक: डीपीसीसी

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली, 16 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने राष्ट्रीय राजधानी में यमुना और अन्य जलाशयों में मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगा दी है। गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा के मद्देनजर विसर्जन केवल स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही किया जा सकेगा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मई 2020 के संशोधित दिशानिदेशों के तहत जारी इन निदेशों में डीपीसीसी ने स्पष्ट किया कि 'प्लास्टर ऑफ पेरिस' (पीओपी) से बनी मूर्तियों को जलाशयों में विसर्जित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मूर्तियों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक रंगों और पेंट में पारा, क्रोमियम, सीसा और कैडमियम जैसे जहरीले तत्व हो सकते हैं, जो जलीय जीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के तहत नौ सितंबर को जारी डीपीसीसी के निदेशों में मूर्ति निमार्ताओं और विक्रेताओं को केवल सामान्य मिट्टी, आसानी से गलने वाली सामग्री और प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करने को कहा गया है। डीपीसीसी ने कहा कि मूर्तियों के विसर्जन से पानी में गाद जमा होती है और जल की गुणवत्ता खराब होती है।

समिति ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के 13 जनवरी और 16 सितंबर 2015 के उन आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि निर्धारित स्थानों को छोड़कर यमुना नदी में कचरा, पूजा सामग्री, खाद्यान्न, तेल अन्य सामग्री डालना प्रतिबंधित है।

आदेश के अनुसार, सभी जिलाधिकारियों को इन नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 रुपये का जुमार्ना लगाया जाएगा, जो डीपीसीसी के पास जमा होगा। जल अधिनियम की धारा 33ए के तहत जारी निदेशों के उल्लंघन पर छह साल तक की जेल और जुमार्ने की सजा हो सकती है।

अंडरगारमेंट में छिपाकर लाया 1.346 किलो सोना बरामद, बांग्लादेशी यात्री गिरफ्तार

नई दिल्ली, 16 सितंबर (वेब वार्ता)। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने 1.346 किलोग्राम सोने की तस्करी के मामले में बांग्लादेश के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। बरामद सोने की कीमत करीब 1.88 करोड़ रुपये बताई गई है। आरोपी यात्री सोने को रासायनिक पेस्ट के रूप में अंडरगारमेंट में छिपाकर लाया था।

सीमा शुल्क विभाग के अनुसार, यात्री 12 सितंबर को जेद्दा से एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई2256 से दिल्ली पहुंचा था। इसके बाद उसे दिल्ली से ढाका की उड़ान एआई237 से रवाना होना था। अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट क्षेत्र में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के अधिकारियों ने जांच के दौरान उसे रोका। तलाशी में यात्री के अंडरगारमेंट के भीतर तीन भूरे-सफेद रंग के अंडाकार आकार के कैप्सूल मिले। इनमें रासायनिक पेस्ट के रूप में सोना छिपाकर रखा गया था। पैकिंग समेत इनका कुल वजन करीब 1,596 ग्राम था। यात्री को विमान से उतारकर सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों के पास लाया गया। रासायनिक पेस्ट से सोना अलग करने की प्रक्रिया के बाद दो आयताकार आकार की सोने की छड़ें बरामद हुईं।

सत्य निकेतन घटना को लेकर अभाविप का कांग्रेस- एनएसयूआई पर हमला

कहा- विद्यार्थियों की समस्या का समाधान नहीं, मुद्दा चाहिए

नई दिल्ली, 16 सितंबर (वेब वार्ता)। सत्य निकेतन की घटना और विद्यार्थियों के लिए 10 हजार क्षमता वाले छात्रावास के निर्माण की घोषणा को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने कांग्रेस-एनएसयूआई पर निशाना साधा। अभाविप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस-एनएसयूआई विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान चाहने के बजाय उन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना चाहती है।

अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि सत्य निकेतन की घटना के समय मलबे पर हथौड़ा चलाकर रील बनाने से लेकर अब 10 हजार विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा पर सवाल उठाने तक कांग्रेस-एनएसयूआई लगातार विद्यार्थियों की समस्याओं पर राजनीति कर रही है।

उन्होंने कहा कि जब छात्रावासों की कमी थी, तब कांग्रेस-एनएसयूआई इस विषय को लेकर राजनीति करती थी और अब जब विद्यार्थियों की मांग पर छात्रावास निर्माण की घोषणा हुई है, तो उसके निर्माण पर ही प्रश्न उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस-एनएसयूआई से स्पष्ट करने को कहा कि वह विद्यार्थियों की समस्या का समाधान चाहती है या केवल इस विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना चाहती है।

सार्थक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद 50 से अधिक वर्षों तक दिल्ली में शासन किया है। कांग्रेस-एनएसयूआई को यह सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए कि इतने लंबे शासनकाल के दौरान विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और सुलभ छात्रावास उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के आवास जैसे गंभीर विषय को राजनीति का साधन बनाने के बजाय उनकी वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अभाविप लंबे समय से छात्रावासों की संख्या बढ़ाने और विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं सुलभ आवास उपलब्ध कराने की मांग करती रही है।

डूसू चुनाव 2026-27 से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर डीयू कुलपति ने की बैठक

नई दिल्ली, 16 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव 2026-27 के सुचारू रूप से संचालन हेतु विश्वविद्यालय अधिकारियों, कॉलेजों के प्रिंसिपलों, हॉल्स और हॉस्टलों के प्रोवोस्ट और पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई।

...महिला कॉन्स्टेबलों की तैनाती का भी इंतजाम होगा

वोटों की गिनती दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पस हॉल में 19 सितंबर को होगी। चुनाव के दौरान संवेदनशील जगहों पर हिंसा की किसी भी घटना को रोकने के लिए 18 सितंबर तक रात में गश्त जारी रहेगी। वोटिंग के दिन कॉलेजों एवं विभागों एवं संस्थानों के बाहर पुलिस गश्त का प्रबंध होगा। इसके अलावा, महिला कॉलेजों में महिला कॉन्स्टेबलों की तैनाती का भी इंतजाम होगा।

डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने डूसू चुनाव की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही चुनाव को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि डूसू चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होने चाहियें। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके शिक्षकों के लिए सभी विद्यार्थी बराबर हैं। कुलपति ने शिक्षकों से अपील की कि वे किसी भी तरह के पक्षपात से बचें। उन्होंने कहा कि डूसू चुनाव शांतिपूर्ण और ठीक-ठाक से हों, इसके लिए सभी संबंधित लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं।

प्रो. योगेश सिंह ने सभी प्रिंसिपलों से अपील की कि वे अपने-अपने कॉलेजों में अगले 3-4 दिनों तक सुरक्षा को बढ़ाए रखें। सभी कॉलेज अपने यहां एक-एक शिक्षक को नियुक्त करें, जोकि डूसू चुनाव प्रक्रिया के दौरान पुलिस के साथ लाइजनिंग का काम करें। कुलपति ने कहा कि चुनाव प्रबंधों में शिक्षकों की ज्यादा भागीदारी होने से चुनाव अच्छे से सम्पन्न होंगे।

इस अवसर पर डीन ऑफ कॉलेज प्रो. बलराम पाणी, साउथ कैंपस की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी, रजिस्ट्रार डॉ विकास गुप्ता, कल्चर काउंसिल के अध्यक्ष एवं पीआरओ अनूप लाठर, मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा, मुख्य रिटर्निंग अधिकारी डॉ. राजेश सिंह और दिल्ली पुलिस की ओर से कई अधिकारियों सहित डीयू के विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपल, विभागाध्यक्ष और विभिन्न छात्रावासों के प्रोवोस्ट व वार्डन आदि भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान बताया गया कि चुनाव से एक दिन पहले कॉलेजों को ईवीएम पहुंचाई जाएंगी। ईवीएम भेजने का काम सुबह आठ बजे शुरू होगा और इसके लिए तैनात मास्टर ट्रेनर इन्हें पहुंचाएंगे। डूसू चुनाव के लिए वोटिंग 18 सितंबर को होगी। वोटिंग का समय डे-क्लास के लिए सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर एक बजे तक और इवनिंग क्लास के लिए दोपहर तीन बजे से शाम साढ़े सात बजे तक है। वोटिंग के बाद, ईवीएम को छात्र प्रतिनिधियों और चुनाव अधिकारी की मौजूदगी में उनके बक्सों में सील किया जाएगा और दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पस हॉल (यूनिवर्सिटी इंडोर स्टेडियम) में जमा किया जाएगा।

यातायात नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने काटे 2,511 चालान

नई दिल्ली, 16 सितंबर (वेब वार्ता)। राजधानी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उत्तरी रेंज ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को बड़े स्तर पर कार्रवाई की। अलग-अलग इलाकों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 2511 चालान काटे। इनमें सबसे ज्यादा कार्रवाई सड़क किनारे गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ हुई। गलत पार्किंग के 2041 चालान काटे गए।

पुलिस के मुताबिक, अभियान डीसीपी ट्रैफिक उत्तरी रेंज डॉ. सचिन कुमार सिंघल की निगरानी और निर्देशन में चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई की गई। सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़े करने से यातायात प्रभावित होने के साथ-साथ कई जगह जाम की स्थिति बनती है। इसी को देखते हुए गलत पार्किंग पर विशेष जोर दिया गया। अभियान के दौरान गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। ऐसे वाहन चालकों के 383 चालान काटे गए। गलत दिशा में वाहन चलाना सड़क हादसों की आशंका बढ़ाने के साथ दूसरे वाहन चालकों के लिए भी खतरा पैदा करता है। इसके अलावा वाहनों के शीशों पर नियमों के विपरीत टिंटेड ग्लास का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस तरह के 87 चालान किए।

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, अभियान का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि सड़कों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर करना, कैरिजवे पर अनावश्यक अवरोध रोकना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए ट्रैफिक कर्मियों को संवेदनशील और ऐसे स्थानों पर लगातार मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं, जहां नियमों का उल्लंघन अधिक होता है। अधिकारियों ने कर्मचारियों को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा है। उत्तरी रेंज ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि सड़क पर यातायात अनुशासन बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर हर घर में आशीर्वाद का दीया जलाने का आह्वान किया

नई दिल्ली, 16 सितंबर (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर उनके अच्छे स्वास्थ्य व दीघार्यु के लिए आशीर्वाद का दीया जलाने का बुधवार को आग्रह किया।

भाजपा और दिल्ली सरकार 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ह्यसेवा संकल्प अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महीने भर चलने वाले अभियान के दौरान 13,800

करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की शुरूआत की घोषणा की थी। गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किए एक वीडियो में दिल्ली के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर अपना आशीर्वाद प्रदान करने का आह्वान किया।

निरंतर प्रार्थना करें

उन्होंने कहा, मैं हर परिवार से अपील करती हूं कि वे 17 सितंबर को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आशीर्वाद का दीया जलाएं और उनके अच्छे स्वास्थ्य, दीघार्यु और मां भारती की सेवा में निरंतर शक्ति के लिए प्रार्थना करें।

कनॉट प्लेस के आसपास शाम 6.30 बजे के बाद रेहड़ी-पटरी पर रोक

नई दिल्ली, 16 सितंबर (वेब वार्ता)। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने राजधानी के कनॉट प्लेस और उसके आस पास के वह क्षेत्र जो 'नो-वेंडिंग जोन' में हैं वहां रेहड़ी पटरी पर रोक लगाई है। एनडीएमसी ने यहां अतिक्रमण रोधी अभियान चलाने का आदेश दिया है। अधिकारियों के अनुसार, लुटियंस दिल्ली के अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में निर्धारित समय शाम 6.30 बजे के बाद रेहड़ी-पटरी लगाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

16 घंटे में सुलझा हत्या का मामला, मर्डर के आरोप में पति गिरफ्तार

नई दिल्ली, 16 सितंबर (वेब वार्ता)। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के आनंद पर्वत थाना पुलिस ने एक महिला की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए घटना के करीब 16 घंटे के भीतर उसके पति को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक, तकनीकी जांच और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई खुफिया जानकारी की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई गई।

पुलिस के अनुसार, मृतका की उम्र 32 वर्ष थी और वह पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर, आनंद पर्वत इलाके में अपने पति, दो बेटियों और मां के साथ रहती थी। 14 सितंबर को आनंद पर्वत थाना पुलिस को एक महिला की संदिग्ध मौत की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। महिला एक कमरे में मृत अवस्था में मिली।

पुलिस के मुताबिक, मृतका की करीब 10 वर्षीय बेटी ने बताया कि तड़के लगभग 3:45 से 4 बजे के बीच उसकी नींद खुली थी। उसने अपने पिता को अपनी मां के पास देखा था। बच्ची के अनुसार, पिता कुछ देर बाद घर से बाहर चले गए। बाद में मां द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं देने की बात सामने आई। शव की शुरूआती जांच में गर्दन के बाईं ओर नाखून जैसे निशान पाए गए, जबकि शरीर पर बाहर से कोई अन्य स्पष्ट चोट नहीं दिखाई दी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य व तस्वीरें दर्ज कीं। महिला को एलएचएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखा गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल की परिस्थितियों और नाबालिग बेटी के बयान के आधार पर मृतका के पति की भूमिका संदिग्ध लगी। इसके बाद आनंद पर्वत थाने में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की। पुलिस के मुताबिक, करीब 16 घंटे के भीतर आरोपी चंद्रपाल भाटी (24) को बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से पकड़ लिया गया और बाद में मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या में भूमिका स्वीकार की। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि दोनों के बीच वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण थे और अक्सर विवाद होता था। पुलिस के मुताबिक, इसी तरह के एक विवाद के बाद आरोपी ने कथित रूप से पत्नी का गला घोंट दिया। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

विहिप ने अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी का लोगो किया जारी

नई दिल्ली, 16 सितंबर (वेब वार्ता)। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर उनके जीवन, कार्यों और सांस्कृतिक योगदान को स्मरण करने के लिए विशेष लोगो जारी किया।

इस लोगो को जारी करते हुए विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महा-मंत्री बजरंग लाल बागड़ा ने कहा यह लोगो उनके आध्यात्मिक संस्कारों, हिंदू समाज के गौरव-जागरण तथा भारतीय संस्कृति के प्रति आजीवन समर्पण को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि लोगो में अंकित अशोक सिंघल नाम श्रद्धा और सम्मान का भाव प्रकट करता है, जबकि जन्म शताब्दी वर्ष 1926झ 2015 उनके जीवन-काल को रेखांकित करता है। 27 सितंबर को उनके जन्म के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जारी यह लोगो उनके विचारों, संकल्पों और कार्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा।

उन्होंने बताया कि लोगो की भगवा-केसरिया पृष्ठभूमि त्याग, तपस्या, आध्यात्मिक चेतना, शौर्य और राष्ट्रधर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। चारों ओर बना स्वर्णिम वलय भारतीय ज्ञान-परंपरा की शाश्वतता, गौरव और प्रकाश को दशार्ता है। लोगो में अंकित श्रीराम मंदिर श्रद्धेय अशोक सिंघल के जीवन के एक बड़े ध्येय तथा श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में उनके ऐतिहासिक योगदान का प्रतीक है। मंदिर के साथ लहराता भगवा ध्वज सनातन परंपरा, संगठन, त्याग और सांस्कृतिक स्वाभिमान का भाव प्रकट करता है।

विहिप महामंत्री ने कहा कि लोगो के केंद्र में स्थित अशोक सिंघल का शांत, तेजस्वी और सौम्य व्यक्तित्व उनके आध्यात्मिक संस्कार, दृढ़ संकल्प, संगठन-कौशल तथा पूज्य संतों के प्रति श्रद्धा और हिंदू समाज के प्रति उनकी आत्मीयता को दशार्ता है। उनका तिलक और श्वेत वस्त्र सादगी, आध्यात्मिक आस्था और भारतीय जीवन-मूल्यों के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। नाम को उभारता गहरा लालझमरून पट्ट ऊर्जा, साहस, संकल्प और संघर्षशीलता का भाव व्यक्त करता है, जबकि नीचे का पीताभझस्वर्णिम आधार ज्ञान, प्रकाश, मंगल और भविष्य के प्रति आशा का संदेश देता है। बागड़ा ने बताया कि यह लोगो केवल एक दृश्य-चिह्न नहीं, बल्कि अशोक सिंघल के जीवन-संदेश का प्रतीकात्मक संकलन है। उनका जीवन भारतीय संस्कृति, हिंदू समाज के संगठन, पूज्य संतों के प्रति श्रद्धा तथा सांस्कृतिक स्वाभिमान के लिए समर्पित रहा। जन्म शताब्दी वर्ष उनके योगदान के स्मरण के साथ-साथ सेवा, संगठन, संस्कार और सांस्कृतिक चेतना के नए संकल्पों को आगे बढ़ाने का अवसर है। विश्व हिन्दू परिषद समेत सम्पूर्ण विश्व के लोग जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान इस लोगो का उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों, प्रकाशनों, डिजिटल माध्यमों, स्मृति अभियानों और जनसंपर्क गतिविधियों में किया जाएगा।

नीट विरोध प्रदर्शन: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस लाठीचार्ज संबंधी याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 16 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से जुड़े प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के आरोप से इनकार करने के दिल्ली पुलिस के दावे को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि पुलिस के इस दावे के विपरीत मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई थीं।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक नागरिक और मीडिया पेशेवर के नाते उसे सच्चाई जानने का अधिकार है, जो जवाबदेही तय करने के लिए आवश्यक है। उसने अदालत से दिल्ली पुलिस को इस मुद्दे पर दिए गए उसके अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका के तहत ऐसे मामलों पर सुनवाई का प्रावधान नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता नितिन नरेश से कहा कि वह यह बताएं कि किस कानून के तहत उन्हें अपने अभ्यावेदन पर निर्णय की मांग करने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि किसी भी याचिकाकर्ता को किसी विवाद या कानूनी/संवैधानिक अधिकार के हनन को साबित करना होता है।

पीठ ने कहा, ह्यहमसमाचार पत्र पढ़कर आपके दिमाग में आने वाली हर चीज जनहित याचिका नहीं बन जाती। जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे बड़े-बड़े शब्दों का इस्तेमाल बिना किसी ठोस आधार के नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, आपकी याचिका क्या है? दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी किया। मीडिया द्वारा उस बयान का खंडन किया गया और आप हमसे जांच का निर्देश देने के लिए कह रहे हैं? कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) ने नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में सरकार से जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के केंद्र जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था अपनी मांगों को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के लिए जंतर-मंतर पर जुटे। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन, भीड़ बढ़ने के बाद जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे।

संक्षिप्त वार्ता

देवरिया में पारिवारिक बंटवारे के विवाद में महिला की पीटकर हत्या

वेब वार्ता, देवरिया

देवरिया जिले के गौरी बाजार क्षेत्र में पारिवारिक बंटवारे के विवाद में एक महिला की पीटकर हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी रूद्रपुर राजेश चतुर्वेदी ने सोमवार को यहां बताया कि 13 सितंबर को जगवंती देवी के घर में पारिवारिक बंटवारे को लेकर पंचायत चल रही थी। इसी दौरान उसके ससुर सुरेन्द्र, सास देवंती देवी, ननद कुमारी आंचल, भसुर अमित तथा परिवार के ही गोलू व जग्गू एकराय हो गये और उसे जान से मारने की नीयत से जगवंती को लात-मुक्कों और डंडों से बेरहमी से पीटने लगे।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही गौरी बाजार पुलिस तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घायल महिला को इलाज के लिए देवरिया मेडिकल कॉलेज भिजवाया। वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। उन्होंने बताया घायल महिला की गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर यहां पोस्टमार्टम कराया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस की टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के स्पष्ट कारणों का पता चल सकेगा।

हिंदी केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा और सांस्कृतिक पहचान

वेब वार्ता, कुशीनगर

किसान इंटर कॉलेज पिपरा बाजार में राष्ट्रीय सेवा योजना (ठरर) की सामान्य इकाई के तत्वावधान में हिंदी दिवस समारोह अत्यंत गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विचार गोष्ठी और काव्य पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने हिंदी भाषा की ऐतिहासिक प्रासंगिकता, दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता तथा वैश्विक पटल पर इसकी मजबूत उपस्थिति पर विस्तार से प्रकाश डाला। समारोह की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. विष्णु प्रताप चौबे ने कहा, "हिंदी केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा और सांस्कृतिक पहचान है। आज हिंदी का विस्तार भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के अनेक देशों में इसे प्रमुखता से बोला, पढ़ा और समझा जा रहा है। आधुनिक तकनीकी युग में भी हिंदी ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है।" संस्थान के हिंदी प्रवक्ता सुनील कुमार पांडेय ने अपनी ओजस्वी कविताओं और व्याख्यान के माध्यम से वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में हिंदी के महत्त्व को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में मातृभाषा के प्रति स्वाभिमान और वैश्विक मंच पर इसकी स्वीकार्यता दोनों को साथ लेकर चलना आवश्यक है।

वेतन सीमा में बढ़ोतरी: नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने का स्वर्णिम अवसर

वेब वार्ता, कानपुर

ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किए जाने से सामाजिक सुरक्षा का दायरा और बढ़ने जा रहा है। यह निर्णय नियोक्ताओं के लिए भी अपने प्रतिष्ठानों में पात्र कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है।

ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त प्रथम शाहिद इकबाल ने बताया कि कानपुर के अंतर्गत लगभग 15 जिले आते हैं और वर्तमान में लगभग 3.3 लाख कॉन्ट्रिब्यूटरी सदस्य हैं। नई वेतन सीमा के साथ-साथ वर्तमान एम्प्लॉईज एनरोलमेंट कैंपेन झ2026 (ईईसी -2026) का लाभ उठाकर नियोक्ता अपने यहाँ कार्यरत पात्र एवं पूर्व में छूटे कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ सकते हैं। कर्मचारी कवरेज और क्षेत्र की कुल सदस्य संख्या में वृद्धि को बल मिलेगा तथा अधिक कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ भी मिल सकेगा।

विश्व ओजोन दिवस पर भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

वेब वार्ता, कानपुर

कानपुर। विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर पं. पृथी नाथ (पी.जी.) महाविद्यालय, कानपुर के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा विद्यार्थियों में ओजोन परत के संरक्षण एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से बुधवार को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय ओजोन-अनुकूल जीवनशैली: छोटे बदलाव, बड़ा प्रभाव रखा गया।

महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अनूप कुमार सिंह ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल किसी एक दिन तक सीमित गतिविधि नहीं है, बल्कि इसे हमारी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को पर्यावरण-अनुकूल आदतें अपनाने तथा समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की संयोजक डॉ. अलका रानी ने कहा, ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए एक प्राकृतिक कवच का कार्य करती है। इसके संरक्षण के लिए केवल नीतियाँ और तकनीकी प्रयास ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवनशैली में छोटे-छोटे पर्यावरण-अनुकूल बदलाव अपनाने होंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. विनोद कुमार द्वारा किया गया।

गिरवी कारोबार पर सवाल! जेवर लौटाने के बजाय 24% चक्रवृद्धि ब्याज का दावा

दलित महिला से जातिसूचक अभद्रता व धमकी के आरोप में मामला दर्ज

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। सोने के जेवर गिरवी रखकर रुपये देने के कारोबार में ब्याज की दर और जेवर वापस करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कोतवाली क्षेत्र के कटरा बाजार में सामने आए मामले में एक दलित महिला ने दो सराफा व्यापारियों पर गिरवी रखे 138 .400 ग्राम सोने के आभूषण वापस मांगने पर कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और परिवार को जान से मरवाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

नेहरूनगर निवासी करीब 45 वर्षीय प्रेमाबाई पत्नी सुनील कुमार सहरिया ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वर्ष 2011 में मकान निर्माण के लिए रुपये की आवश्यकता होने पर उन्होंने अपने पति के साथ कटरा बाजार के सराफा व्यापारियों के यहां पैतृक सोने के आभूषण गिरवी रखे थे।

एफआईआर के मुताबिक 4 अगस्त 2011 को 71 ग्राम सोने के कंगन 1.10 लाख रुपये, 25 अगस्त 2011 को 59.400 ग्राम सोने के कंगन एक लाख रुपये तथा 16 नवंबर 2011 को आठ ग्राम सोने की अंगूठी 10 हजार रुपये में गिरवी रखी गई थी। इस प्रकार कुल 138.400 ग्राम सोने के आभूषण 2.20 लाख रुपये में गिरवी रखे जाने की बात शिकायत में कही गई है।

गिरवी कारोबार के नियम भी जांच का हिस्सा

मामले में अब केवल कथित अभद्रता और धमकी ही नहीं, बल्कि सोने के जेवर गिरवी रखकर रुपये देने के लेन-देन, ब्याज की गणना और 24 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की मांग भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। नियमित रूप से ब्याज पर धन देने के कारोबार पर लागू साहूकारी/मनी-लेंडिंग संबंधी नियम, लेन-देन के दस्तावेज और गिरवी रखे आभूषणों की वापसी की शर्तें भी विवेचना में देखी जा सकती हैं। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

महिला का कहना है कि तय व्यवस्था के अनुसार वह समय-समय पर ऋण का ब्याज भी चुकाती रही। मई 2026 में जब उसने गिरवी रखे आभूषण वापस मांगे तो आरोप है कि जेवर लौटाने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद उससे 24 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से रकम चुकाने की बात कही गई। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया।

बाजार में रोककर जातिसूचक गाली देने का आरोप

शिकायत के अनुसार 9 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 12 बजे प्रेमाबाई अपने पति के साथ बाजार से गुजर रही थीं। आरोप है कि कटरा बाजार निवासी सेठ महेन्द्र कुमार पुत्र हीरालाल और उनके पुत्र अमित उर्फ गोल्डी ने उन्हें रोक लिया। महिला का आरोप है कि पूर्व में पुलिस से शिकायत करने से नाराज होकर दोनों ने सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसका अपमान किया। दोबारा पुलिस में शिकायत करने पर परिवार को जान से मरवाने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है।

स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने के बाद प्रेमाबाई ने रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(घ), 3(1)(द) तथा बीएनएस की धारा 351(3), 352 और 316(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

धार्मिक अनुष्ठान के साथ मनाया जगद्गुरुश्री राजेंद्र दास देवाचार्यजी महाराज का प्राकट्योत्सव

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ऋषि पंचमी पर श्रीलक्ष्मी नृसिंह मंदिर में दो दिवसीय आयोजन, हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

ललितपुर। ऋषि पंचमी के अवसर पर जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री अग्रवीणधीश्वर एवं श्री मलूक पीठाधीश्वर स्वामी श्रीराजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज का प्राकट्योत्सव स्थानीय श्रीलक्ष्मी नृसिंह मंदिर में दो दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के साथ श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मनाया गया। आयोजन के दौरान अखंड श्रीरामचरितमानस पाठ, हवन, भगवान का अभिषेक एवं श्रृंगार सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। धार्मिक कार्यक्रमों के उपरांत विशाल प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तजनों ने सहभागिता कर प्रसाद ग्रहण किया। उपस्थित संतों एवं वक्ताओं ने प्राकट्योत्सव को ललितपुर नगर का सौभाग्य बताते हुए कहा कि पूज्य महाराज जी श्रीलक्ष्मी नृसिंह मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं और संपूर्ण संत समाज में उनका विशिष्ट स्थान है। संपूर्ण वैदिक अनुष्ठान कृष्णदेव लिटोरिया व प्रमोद लिटोरिया के सानिध्य में संपन्न कराए गए। इस अवसर पर महंत रामबालक दास जी महाराज, महंत श्री रामदास जी महाराज, संत श्री अनंतदास जी महाराज, संत श्री राम लेखनदास जी महाराज सहित जिला अध्यक्ष हरीश चंद्र रावत, अशोक गोस्वामी, अशोक पटेरिया, वी.के. सरदार, विलास पटैरिया, धर्मेंद्र रावत, कमला पत रिछारिया, राजीव बबेले, गिरीश पाठक, गजेंद्र वाजपेयी, विवेक सरैया, ह्रदेश हुण्डैत, आलोक चतुर्वेदी, प्रदीप रिछारिया, कृष्णकांत सोनी,हरिशंकर साहू, अमित संज्ञा, शिब्बू राठौर, प्रशांत शुक्ला, मनीष दुबे, नेहाल सेन, मानू शर्मा, नीरज शर्मा, गोलू चौबे, राहुल चौबे, मुकेश गुप्ता, गोलू सरदार, रानू कुशवाहा, अंकित कुशवाहा, कमलेश सेन सहित संकल्प अकादमी के छात्र-छात्राएं सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

ईवीएम की एफएलसी तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा, पारदर्शिता और सुरक्षा पर जोर

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जिलाधिकारी अनुनय झा ने बुधवार को निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने एफएलसी के लिए चयनित हाल का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एफएलसी का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाए। एफएलसी हाल में अधिकृत व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रखने को कहा गया। उन्होंने सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के साथ ही सभी आवश्यक अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की निर्धारित गाइडलाइन और निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए एफएलसी से जुड़ी सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएं।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा-2026 को लेकर समन्वय बैठक आयोजित

वेब वार्ता, कमर खान

बलरामपुर। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा-2026 कार्यक्रम के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर में समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक आदर्श नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉ.धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के निर्देशन में अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सभासदों,सफाई कर्मियों एवं नगर पालिका के कर्मचारियों ने सहभागिता की।

बैठक में स्वच्छता में सहभागिता,स्वच्छ भारत में विकसित भारत अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वच्छता को

जन-जन के व्यवहार का हिस्सा बनाने तथा नगर को स्वच्छ,सुंदर एवं स्वस्थ बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी पर विशेष जोर दिया गया।

अभियान के प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों एवं सार्वजनिक स्थलों का रूपांतरण,स्वच्छता पाठशाला,स्वच्छता के लिए युवा,सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर,स्वच्छता के लिए जनभागीदारी तथा स्वच्छता से समृद्धि जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में कहा गया कि स्वच्छता केवल नगर पालिका या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है,बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों,कर्मचारियों,सफाई मित्रों,युवाओं एवं आम नागरिकों के सामूहिक सहयोग से स्वच्छता अभियान को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

इस अवसर पर उपस्थित सभासदों,सफाई कर्मियों एवं नगर पालिका कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। सभी ने नगर को स्वच्छ रखने,सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी न फैलाने,स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने का संकल्प लिया।

राजकीय पॉलिटेक्निक में शुरू हुई प्रेरणा कैंटीन

लक्ष्मीकान्त पाठक/हरदोई। राजकीय पॉलिटेक्निक, हरदोई में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित प्रेरणा कैंटीन का शुभारंभ किया। कैंटीन का संचालन विकासखंड बावन की ग्राम पंचायत तत्यौरा द्वारा पतंजलि महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। प्रेरणा कैंटीन से राजकीय पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत 73 छात्र एवं 17 छात्राओं समेत कुल 90 विद्यार्थियों को स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कैंटीन के संचालन से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।

सोती पत्नी पर टूटा पति का कहर, शक में धारदार हथियार से हत्या; हरदोई में सनसनी

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। रिश्तों की डोर जब विश्वास के बजाय शक की गांठ में उलझ जाए तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है, टीलिया मोहल्ले की यह घटना उसका दर्दनाक उदाहरण बन गई। जिस घर में पति-पत्नी के साथ जीवन की उम्मीदें सांस ले रही थीं, वहीं बुधवार तड़के कथित तौर पर धारदार हथियार ने एक महिला की जिंदगी छीन ली। पति पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

शहर कोतवाली क्षेत्र के टीलिया मोहल्ले में परवेज और उसकी पत्नी नगमा

रहते थे। बताया जा रहा है कि पति को पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने का शक था। यही शक धीरे-धीरे रिश्ते के बीच ऐसी दीवार बन गया, जिसके पीछे विश्वास दम तोड़ता चला गया।

बुधवार तड़के करीब पांच बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली। बताया गया कि नगमा घर में सो रही थी, तभी उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू की। पुलिस ने आरोपी पति परवेज को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

प्रारंभिक जानकारी में हत्या की वजह पत्नी के चरित्र को लेकर पति का शक बताया जा रहा है। हालांकि घटना के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं, वारदात कैसे हुई और इसमें कौन-कौन से पहलू जुड़े हैं, इसका खुलासा पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा।

एक ओर एक जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई, तो दूसरी ओर शक की एक चिंगारी ने पूरे परिवार को गहरे अंधेरे में धकेल दिया। फिलहाल पुलिस मामले की हर कड़ी जोड़ने में जुटी है।

डीएम ने संपत्ति के स्टाम्प मूल्यांकन का किया स्थलीय सत्यापन

निर्धारित स्टाम्प मूल्य के अनुरूप ही संपत्तियों का पंजीकरण कराने के दिए निर्देश

वेब वार्ता,देवरिया। देवरिया जिले में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सोमवार को संपत्तियों के क्रय-विक्रय में निर्धारित स्टाम्प मूल्यांकन की वास्तविकता जांचने के लिए एआईजी स्टाम्प एवं सब रजिस्ट्रार के साथ कसया ढाला फ्लाईओवर के निकट स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने करीब एक करोड़ 15 लाख रुपये की विक्रय संपत्ति का मौके पर सत्यापन किया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित संपत्ति के निचले तल पर व्यावसायिक उपयोग था, जबकि ऊपरी तल आवासीय उपयोग में था। उक्त संपत्ति

का निर्धारित स्टाम्प मूल्य सात लाख रुपये था। जिलाधिकारी ने मौके की वास्तविक स्थिति का स्टाम्प अभिलेखों में दर्ज विवरण के अनुसार मिलान किया तथा लागू स्टाम्प मूल्य दर की जांच की। सत्यापन में मौके की स्थिति और अभिलेखों में दर्ज विवरण सही पाया गया।

जिलाधिकारी ने उपनिबंधक अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपत्तियों के क्रय-विक्रय में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार स्टाम्प मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए। नियमानुसार परीक्षण के बाद ही विक्रय विलेखों का पंजीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती जाए, ताकि स्टाम्प मूल्यांकन अथवा स्टाम्प शुल्क में किसी प्रकार की कमी न हो। निरीक्षण के दौरान एआईजी स्टाम्प अजय धर्मराज सिंह और सब रजिस्ट्रार अजय कुमार सिंह उपस्थित रहे।

देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र में तैनात आशा कर्मियों की नौकरी जायेगी

वेब वार्ता, देवरिया। देवरिया जिले में रुद्रपुर क्षेत्र में तैनात आशा कर्मियों के निष्क्रियता के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रुद्रपुर के चिकित्सा अधीक्षक ने संबंधित आशा चयन समितियों के अध्यक्ष ग्राम प्रधानों को पत्र भेजकर निष्क्रिय आशाओं का चयन निरस्त करने और उनके स्थान पर नई आशा कार्यकर्ता का चयन करने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में स्वास्थ्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बृजवासी सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान नौ गांवों में तैनात आशा कार्यकताओं के निष्क्रिय पाए जाने का मामला सामने आया है। समीक्षा में पाया गया कि संबंधित आशाओं ने अप्रैल से अगस्त तक एक भी प्रसव नहीं कराया। प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को एक हजार की आबादी पर प्रतिमाह तीन प्रसव कराने चाहिए। इस मानक के अनुसार पांच माह में एक आशा कार्यकर्ता को कम से कम 15 प्रसव कराने थे। समीक्षा में संबंधित आशाओं की ओर से निर्धारित दायित्वों का अपेक्षित रूप से निर्वहन नहीं किया जाना पाया गया। जिसमें जगरनाथपुर,खोरमा, नगवा, कोरवा, हौली ,बलिया, मदनपुर, गोविंदपुर, और डाला गांव में तैनात आशा निष्क्रिय पाई गई।

कुशीनगर में एथेनॉल उत्पादन की प्रस्तावित परियोजना गन्ना नहीं मिलने से अटका एक लाख लीटर एथेनॉल प्लांट

वेब वार्ता, कुशीनगर

कुशीनगर जिले के खड्डा में प्रतिदिन एक लाख लीटर एथेनाल उत्पादन की प्रस्तावित परियोजना के लिए कागजी और तकनीकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। धन का भी पूरा इन्तजाम है लेकिन पर्याप्त गन्ना नहीं मिलने से परियोजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है। आईपीएल चीनी मिल की पेराई क्षमता 45 लाख क्विंटल है, जबकि बीते पेराई सत्र में मिल को करीब 27 लाख कुंतल गन्ना ही मिल सका।

जानकारों का कहना है कि गन्ने की कमी एथेनाल प्लांट की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता कम नहीं है, लेकिन मिल को अपेक्षित मात्रा में गन्ना नहीं मिल रहा है। मिल गेट और आसपास के कई क्रय केंद्र दूसरे मिलों को आवंटित होने से आईपीएल की गन्ना उपलब्धता प्रभावित होती है।

एथेनाल संयंत्र का मुख्य कच्चा माल गन्ने की पेराई से निकलने वाला शीरा है। इसलिए पर्याप्त गन्ने के बिना संयंत्र का नियमित संचालन संभव नहीं है। 100 किलोलीटर यानी एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले संयंत्र के लिए जमीन का चयन, भूमि परीक्षण सहित जरूरी तकनीकी और कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आईपीएल ने करीब डेढ़ अरब रुपये से ज्यादा खर्च करने का मन भी बनाया हुआ है।

औद्योगिक विकास को झटका

इन दिनों पेट्रोल में एथेनाल की

मात्रा बढ़ाने और वैकल्पिक ईंधन के रूप में इसके इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है। केंद्र और प्रदेश सरकारें इसके उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं। ऐसे समय में खड्डा में प्रस्तावित संयंत्र का अटकना क्षेत्र के लिए औद्योगिक विस्तार के लिए झटका है। संयंत्र लगने पर शीरे का स्थानीय उपयोग होने के साथ रोजगार, परिवहन और अन्य कारोबारी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

खड्डा में एथेनाल प्लांट लगाने की कवायद फरवरी 2020 में शुरू हुई थी। तत्कालीन एडीएम विंध्यवासिनी राय की अध्यक्षता में आईपीएल के उच्चाधिकारी विशाल सोनक, प्रदूषण बोर्ड के वैज्ञानिक राममिलन वर्मा, पर्यावरण सलाहकार मनोज गर्ग व किसानों के साथ बैठक में एथेनाल प्लांट लगाने का निर्णय हुआ था।

तब 60 किलोलीटर एथेनाल व ढाई मेगावॉट बिजली बनाने की योजना थी। वर्ष 2023 में खड्डा की जनसभा में सीएम ने इसकी चर्चा की थी। बाद में अन्न से भी एथेनाल बनाने की योजना बनी लेकिन इसे रोक दिया गया था।

इस संबंध में एनपी सिंह, प्रधान प्रबंधक, आईपीएल चीनी मिल खड्डा ने बताया कि एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एथेनाल संयंत्र के लिए सभी कागजी और तकनीकी औपचारिकताएं पूरी हैं। मिल परिसर में ही जमीन आरक्षित की गई है। पर्याप्त गन्ना नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से परियोजना पर कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

महत्वपूर्ण ख़बर

बिच्छू महीनों तक भूखा रहकर भी कर सकता है जीवन संघर्ष

- नई दिल्ली। क्या आप जानते है, बिच्छू एक ऐसा जीव है, जो महीनों तक भूखा रहकर भी जीवन के लिए संघर्ष कर सकता है। बिच्छू को आमतौर पर उसके जहरीले डंक के कारण जाना जाता है। बिच्छू की असली खासियत केवल उसका जहर नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की अद्भुत क्षमता भी है। बिच्छू की सबसे अनोखी विशेषताओं में लंबे समय तक बिना भोजन के जीवित रहना शामिल है। भोजन की कमी होने पर इसका उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म काफी धीमा हो जाता है।इससे शरीर की ऊर्जा की खपत कम हो जाती है और वह सीमित ऊर्जा के सहारे लंबे समय तक जीवित रह सकता है।

कुछ प्रजातियों के बिच्छू कई महीनों तक और विशेष परिस्थितियों में लगभग एक साल तक बिना भोजन के जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। पानी और प्रतिकूल वातावरण में भी बिच्छू की सहनशक्ति उल्लेखनीय मानी जाती है। इसके शरीर में मौजूद विशेष श्वसन अंग विषम परिस्थितियों में शारीरिक गतिविधियों को धीमा करने में मदद करते हैं।

वैश्विक विमर्श में भारत को अपनी बौद्धिकता से योगदान देना होगा: जयशंकर

नई दिल्ली। नई दिल्ली के विवेक ऑडिटोरियम में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आईसीडब्ल्यूए) की सिल्वर जुबली धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारत अब वैश्विक चुनौतियों और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने विचार रख रहा है और वैश्विक विमर्श में अपनी बौद्धिकता, अनुभव और शब्दावली से योगदान देना होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे।

जयशंकर ने आईसीडब्ल्यूए को राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा मिलने के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि 1943 में स्थापित यह परिषद अंतरराष्ट्रीय मामलों के अध्ययन और प्रचार-प्रसार के लिए कार्यरत है, जिसे वर्ष 2001 में संसद द्वारा यह विशेष दर्जा प्राप्त हुआ। विदेश मंत्री ने वर्षगांठ को केवल यात्रा का स्मरण नहीं, बल्कि

भविष्य में आईसीडब्ल्यूए की भूमिका पर विचार करने का अवसर बताया, विशेषकर तब जब भारत और दुनिया दोनों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।

उन्होंने रेखांकित किया कि आज भारत पहले से कहीं अधिक देशों और क्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, जिससे हमारे राष्ट्रीय हित वैश्विक हुए हैं और जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। भारत अब वैश्विक चुनौतियों, विशेषकर मानवता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से अपनी राय रखता है। जयशंकर ने जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर पारंपरिक चर्चाएं अक्सर दूसरे देशों के अनुभवों पर आधारित रही हैं, लेकिन एक उभरते हुए राष्ट्र के रूप में भारत को अब विश्व को देखने और समझने के अपने तरीके में अपनी बुद्धिमत्ता, अनुभव, हितों और विचारों को शामिल करना होगा, न कि केवल दूसरों द्वारा बनाए गए ढांचों पर निर्भर रहना चाहिए।

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाए गए नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह घोषणा समावेशी वैश्विक व्यवस्था, बहुपक्षीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे महत्वपूर्ण विषयों को समेटे हुए है। उपराष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि विश्व व्यवस्था में बदलाव जारी रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे वह वैश्विक शांति, प्रगति और समृद्धि की एक मजबूत आवाज के रूप में उभरा है।

ईरान में प्लेन का टायर हवा में उखड़ा, यात्रियों में मची चीख-पुकार

तेहरान। ईरान के आसमान में एक भयावह मंजर देखने को मिला, जब एक विमान का चक्का टेकऑफ के ठीक बाद हवा में उखड़ गया। ईरान के मशहद शहर से करमानशाह के लिए उड़ान भरने वाले सेपेहरान एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान में यह घटना घटित हुई। अभी यात्री कुछ समझ पाते, इससे पहले ही विमान हवा में बुरी तरह हिलने लगा और जोरदार कंपन ने केबिन में अफरा- तफरी मचा दी। कंपन इतनी तीव्र थी कि ओवरहेड कंपार्टमेंट टूट गए और यात्रियों का सामान उनके ऊपर गिरने लगा, जिससे कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी आईं। विमान के भीतर मौजूद लोगों की चीख-पुकार और दहशत का आलम ऐसा था कि कई लोग जान बचाने की आस में जोर-जोर से दुआएं पढ़ने लगे।

डाक मतदान प्रतिबंधों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर भड़के ट्रंप

वॉशिंगटन। अमेरिका में नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले, सुप्रीम कोर्ट द्वारा डाक से मतदान पर नए प्रतिबंध लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों को रोक दिए जाने के बाद ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने इस फैसले को रिपब्लिकनों के लिए एक बड़ा झटका बताया और अदालत के साथ-साथ अपने ही नियुक्त कुछ जजों पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को एक लंबे पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि यह फैसला रिपब्लिकनों के लिए बड़ा झटका है और कोर्ट ने चुनाव की ईमानदारी बचाने में नाकामी दिखाई है। उनके मुताबिक, कट्टरपंथी वामपंथी इस सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं और बहका रहे हैं, जिससे ऐसे फैसले हो रहे हैं जिन्होंने अमेरिका को कम से कम सौ साल पीछे धकेल दिया है।

ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में नियुक्त कुछ जजों की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये वे लोग नहीं हैं जिनसे मैंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए बात की थी। ये तो अपनी असली शक्ल की खोखली परछाईं भर हैं। उन्होंने इस कोर्ट को देश के इतिहास में कुछ सबसे नुकसानदेह और पीड़ादायक फैसले देने वाले कोर्ट के रूप में याद किए जाने की बात कही। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक आपातकालीन आदेश में ट्रंप प्रशासन के नए डाक मतदान नियमों को लागू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले के विस्तृत कारण नहीं बताए, लेकिन यह संकेत दिया कि इस साल ये प्रतिबंध लागू करने की कोशिश अदालत में सफल नहीं होगी। न्यायमूर्ति सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने फैसले पर असहमति जताई। एलिटो ने तर्क दिया कि अमेरिकी डाक सेवा (यूएसपीएस) के पास डाक को नियंत्रित करने का व्यापक अधिकार है और वह ये नियम लागू कर सकती है। हालांकि, न्यायमूर्ति ब्रेट कावानाघ ने यह माना कि ये नियम 2026 के मध्यावधि चुनाव में लागू नहीं होने चाहिए, लेकिन बाद में मामला दोबारा आने पर वे अपना रुख बदल सकते हैं। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि डाक सेवा पर संघीय नियंत्रण है, इसलिए वह चुनावी डाक के नियम तय कर सकती है। नए नियमों में राज्यों को एक जैसा लिफाफा इस्तेमाल करना पड़ता और योग्य मतदाताओं की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करनी पड़ती।

ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई से ठीक पहले आया फैसला

भुवनेश्वर। 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए रवींद्र पाल उर्फ दारा सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

ओडिशा सरकार ने उसकी समयपूर्व रिहाई की याचिका खारिज कर दी है। करीब 25 साल जेल में बिताने के बाद दारा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने उसकी रिहाई की मांग पर दोबारा विचार किया।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हेमंत शर्मा की अध्यक्षता में स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की विशेष बैठक हुई। बैठक में दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई के आवेदन पर विचार किया गया, लेकिन बोर्ड ने इसे मंजूरी नहीं दी। सरकार की ओर से कहा गया कि उसकी रिहाई से क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, क्योंझर जिला प्रशासन ने 28 अगस्त 2026 को बोर्ड को एक रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 15 अगस्त को दारा सिंह

की संभावित रिहाई के समर्थन में 200 से 250 लोग क्योंझर जिला जेल के बाहर एकत्र हुए थे। अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान कथित तौर पर उकसाने वाली नारेबाजी भी हुई। इस घटनाक्रम को देखते हुए सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े पहलुओं को रिहाई के फैसले में महत्वपूर्ण माना गया।

दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई की मांग पहले भी कई बार खारिज हो चुकी है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 2016, 2019, 2020, 2022 और 2023 में भी उसकी अर्जियां कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक तनाव की आशंकाओं के आधार पर नामंजूर की गई थीं।

मामला जनवरी 1999 में क्योंझर जिले के मनोहरपुर गांव में हुई घटना से जुड़ा है। 22-23 जनवरी की दरमियानी रात ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों फिलिप तथा थिमोथी को उस समय जिंदा जला दिया गया था, जब वे एक स्टेशन वैगन में सो रहे थे। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो ने की थी।

सुनवाई पर नजर रहेगी

2003 में सीबीआई की अदालत ने दारा सिंह को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में 2005 में ओडिशा हाईकोर्ट ने उसकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। अब दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। राज्य सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के ताजा फैसले के बाद इस सुनवाई पर नजर रहेगी।

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद 81 साल के वोहरा को मिली राहत

कंपनी ने छोड़ा जमीन पर दावा

मुंबई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड निवासी 81 वर्षीय असगरअली वोहरा को लंबे समय से चले आ रहे जमीन विवाद में राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 8 सितंबर को मुलाकात के कुछ दिन बाद विवादित जमीन से जुड़ी कंपनी सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स ने अपने निर्माण अधिकार से पीछे हटने का कदम उठाया है। कंपनी ने नगर निकाय को पत्र देकर निर्माण शुरू करने की अनुमति यानी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट वापस करने की जानकारी दी है।

वोहरा का दावा है कि उन्होंने गुजरात के वडनगर स्थित बीएन स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पढ़ाई की थी। उन्होंने 8 सितंबर को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर भायंदर पूर्व के नवघर इलाके में जमीन से जुड़े विवाद की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग की थी। उनका कहना है कि वर्षों से चल रहे विवाद के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल सका।

विवाद करीब 2,810 वर्गमीटर के उस भूखंड से जुड़ा है, जिसे वोहरा के अनुसार उन्होंने 1989 में खरीदा था। उनका आरोप है कि 2011 में स्वयं बिल्डर्स और सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स नाम की कंपनियों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। वोहरा ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी जानकारी के बिना कथित तौर पर जाली दस्तावेज तैयार कर जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया। दोनों कंपनियों को भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता से जुड़ा बताया गया है। हालांकि ये आरोप संबंधित पक्षों के रुख और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। अब सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स ने मीरा भयंदर नगर निगम के नगर नियोजन विभाग को पत्र देकर विवादित भूखंड के लिए मिली निर्माण अनुमति वापस करने की प्रक्रिया शुरू की है। कंपनी ने कहा है कि उसने 13 जून 2019 को पंजीकृत दस्तावेज के जरिए जमीन खरीदी थी और 17 अप्रैल 2026 को निर्माण की अनुमति प्राप्त की थी। जमीन के मालिकाना हक से जुड़े विवाद के चलते कंपनी ने अनुमति वापस करने का निर्णय लिया है। मामले में 2015 में पुलिस प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। वोहरा का कहना है कि इसके बाद उन्होंने राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस सहित विभिन्न स्तरों पर शिकायतें कीं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद स्थानीय प्रशासन ने मामले को लेकर सक्रियता दिखाई और 16 सितंबर को संबंधित पक्षों की सुनवाई तय की गई थी। विवाद से जुड़े घटनाक्रम में पुलिस शिकायत वापस लेने को लेकर भी प्रक्रिया आगे बढ़ने की बात सामने आई है। हालांकि इस संबंध में अंतिम स्थिति संबंधित अधिकारियों और पुलिस की औपचारिक कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगी। जमीन के स्वामित्व और पुराने आरोपों पर अंतिम निर्णय संबंधित न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं से तय होगा।

चार दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अब यूसीसी की होगी दस्तक

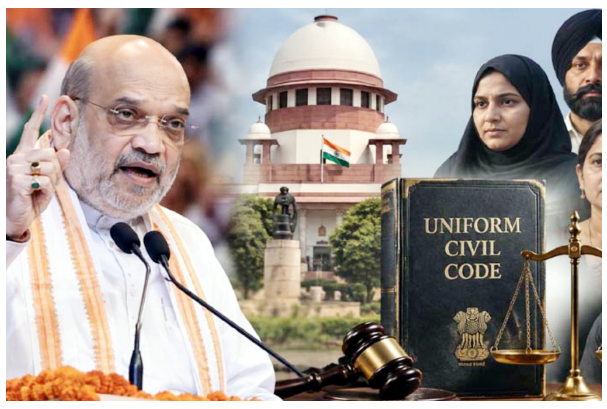

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। शाह ने कहा है कि भाजपा-एनडीए शासित 21 राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी कानून लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, इस घोषणा के तुरंत बाद भाजपा की सहयोगी जेडीयू ने बिहार में यूसीसी लागू करने से इनकार कर दिया। शाह ने तीन तलाक खत्म करने का उदाहरण देते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं और अब यूसीसी भी लागू होगा। यह मुद्दा नया नहीं है, दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से यूसीसी की आवश्यकता पर जोर दे रहा है, लेकिन राजनीतिक नफा-नुकसान के चलते सरकारों ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया।

यूसीसी का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे सिविल मामलों में धर्म-आधारित पर्सनल लॉ की जगह एक समान कानूनी व्यवस्था। इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 44 है, जो नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल है, यानी इसे सीधे अदालत के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता। कानून बनाना संसद या विधानसभाओं का काम है। बावजूद इसके, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों का ध्यान इस ओर खींचा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 1985 के मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में यूसीसी की जरूरत पर जोर दिया था। यह फैसला मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता अधिकार से जुड़ा था और इसने यूसीसी को राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख संवैधानिक मुद्दे के रूप में स्थापित किया। इसके बाद, 1995 के सरला मुद्गल बनाम भारत सरकार मामले में कोर्ट ने फिर सरकार को याद दिलाया कि विवाह और उत्तराधिकार जैसे मामले धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के हैं और अनुच्छेद 44 पर ह्यफ्रेश तरीके से फैसलाह्न लेने को कहा। 2003 में जॉन वल्लमट्टम बनाम भारत सरकार और 2019 में जोस पाउलो कुटिन्हो बनाम मारिया लुइज वैलेंटिना पेरेइरा मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने संसद को कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। हालिया सुनवाई में भी कोर्ट ने महिलाओं के समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी को एक प्रभावी रास्ता बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि इसे लागू करना विधायिका का ही काम है।

सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के बार-बार कहने के बावजूद सरकारों ने इस पर कदम क्यों नहीं उठाए? इसकी मुख्य वजहें राजनीतिक संवेदनशीलता, अल्पसंख्यक समुदायों की आशंकाएं और यूसीसी का असल स्वरूप तय करने की जटिलता रही हैं। पर्सनल लॉ में बदलाव धार्मिक पहचान और सामाजिक परंपराओं से जुड़ा होने के कारण हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। सरकारों को डर रहा कि बिना पर्याप्त बातचीत के इसे लागू करने पर धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा, विभिन्न धर्मों के नियमों को एक समान कानून में ढालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है।

ग्लोबल वॉर्मिंग ने हिंद-प्रशांत महासागरों के बीच प्राकृतिक संबंध को किया कमजोर

नई दिल्ली। दुनिया के मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच पिछले करीब 400 सालों से बना प्राकृतिक तालमेल अब टूटता नजर आ रहा है। वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बदलाव को लेकर चेतावनी जारी की गई है। एक अध्ययन के मुताबिक इंसानी गतिविधियों से बढ़ रही ग्लोबल वॉर्मिंग ने दोनों महासागरों के बीच उस प्राकृतिक संबंध को कमजोर कर दिया है, जिसके आधार पर दुनिया के कई हिस्सों में बारिश, सूखा और तूफानों के पैटर्न को समझा जाता रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच वायुमंडलीय हवाओं का एक संबंध है, जिसे वॉकर सर्कुलेशन और क्लाइमेट कपलिंग के जरिए समझा जाता है। प्रशांत महासागर में अल नीनो या ला नीना जैसी घटनाएं होने पर उनका प्रभाव हिंद महासागर और उसके आसपास के मौसम पर भी पड़ता था। इसी संबंध का असर मानसून और

दुनिया के कई क्षेत्रों में बारिश के स्वरूप पर दिखाई देता था।

वैज्ञानिकों ने बताया कि 1980 के दशक के बाद इस प्राकृतिक व्यवस्था में असामान्य बदलाव देखने को मिले। हिंद महासागर ने प्रशांत महासागर से मिलने वाले जलवायु संकेतों पर पहले की तरह प्रतिक्रिया देना कम कर दिया। समस्या यह थी कि आधुनिक मौसम संबंधी रिकॉर्ड केवल सीमित अवधि के हैं। इसलिए शोधकर्ताओं के लिए यह तय करना कठिन था कि बदलाव प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है या किसी बड़े परिवर्तन का संकेत। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए वैज्ञानिकों ने पेड़ों के छल्लों, प्राचीन मूंगों और गुफाओं में बने स्टैलेग्माइट्स जैसे पेलियोक्लाइमेट रिकॉर्ड का अध्ययन किया। इन प्राकृतिक अभिलेखों में सदियों पुराने तापमान और बारिश से संबंधित संकेत सुरक्षित रहते हैं। इनके आधार पर वैज्ञानिकों ने करीब 1600 से लेकर आधुनिक दौर तक दोनों महासागरों के व्यवहार की तुलना की।

अध्ययन में सामने आया कि पिछले 400 सालों में दोनों महासागरों का संबंध मुख्य रूप से स्थिर रहा। केवल 1810 से 1850 के बीच ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण यह संबंध अस्थायी रूप से कमजोर पड़ा था। ज्वालामुखियों से निकली राख और गैसों ने सूर्य की रोशनी को प्रभावित किया, जिससे वैश्विक तापमान में अस्थायी गिरावट आई। बाद में वातावरण साफ होने पर समुद्री जलवायु प्रणाली फिर सामान्य हो गई। वर्तमान स्थिति इससे अलग है। कोयला, तेल और गैस के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से बढ़ रही ग्रीनहाउस गैसों ने पृथ्वी को लगातार गर्म किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बदलाव का असर मौसम की भविष्यवाणी पर भी पड़ सकता है।

विंध्य के पर्यटन स्थलों पर खूबसूरत नजारों के साथ मिलेगा लजीज खाना

नई दिल्ली। विंध्य क्षेत्र के प्रमुख ईको पर्यटन स्थलों पर अब पर्यटकों को प्राकृतिक नजारों के साथ स्थानीय स्तर पर तैयार शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध होंगे। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं पर्यटन स्थलों पर फूड कार्ट संचालित करेंगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ पर्यटकों के लिए खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराना है।

उत्तर प्रदेश का जिला मिरजापुर जनपद के विंढमफाल, सिरसी फाल, लखनिया दरी, सिद्धनाथ दरी समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर फूड कार्ट का निर्माण कराया जाएगा। इन स्थानों पर हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक प्राकृतिक छटा का आनंद लेने पहुंचते हैं। फिलहाल कई पर्यटन स्थलों पर खान-पान की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण पर्यटकों को परेशानी होती है। उन्हें या तो खाने-पीने की सामग्री साथ लानी पड़ती है या फिर सीमित विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। फूड कार्ट शुरू होने के बाद पर्यटक परिवार के साथ बैठकर जलपान कर सकेंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यहां चाट, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, चाय, कॉफी, पावभाजी समेत अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराएंगी। इससे पर्यटकों को भोजन की सुविधा मिलने के साथ महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा।

स्थानीय अधिकारियों का कहना है, कि इस राष्ट्रीय योजना के जरिए महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से पहले से ही बड़ी संख्या में महिलाएं अलग-अलग गतिविधियों से जुड़ी हैं। जिले में 16,259 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है।

पहले थम्स अप, फिर अभद्र इशारे; विरोध पर कार से टक्कर, हादसे के बाद सदमे में पीड़िता

गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड पर हुए हिट एंड रन मामले में महिला बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया ने कार सवारों पर अभद्र व्यवहार और टक्कर मारने के आरोप लगाए हैं। शिवानी के मुताबिक, कार चालक ने पहले बाइकर्स के समूह की ओर थम्स अप का इशारा किया और इसके बाद कथित तौर पर अभद्र इशारे करते हुए बाइक रोकने की कोशिश की। विरोध करने पर कार से उनकी बाइक को टक्कर मार दी गई। हादसे के बाद वह शारीरिक चोटों के साथ मानसिक सदमे से भी जूझ रही हैं।

घटना रविवार सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। शिवानी अपने करीब 20-25 बाइकर्स के समूह के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर राइडिंग कर रही थीं। परिवार के मुताबिक, करीब आठ-नौ किलोमीटर आगे जाने के बाद एक कार चालक तेजी से ओवरटेक कर ग्रुप के आगे पहुंचा। आरोप है कि पहले उसने थम्स अप किया, लेकिन इसके बाद कार की गति अचानक कम कर दी।

परिवार का कहना है कि दूरी बनाए रखने के लिए शिवानी ने भी बाइक की रफ्तार कम की। इसी दौरान कार चालक ने कथित तौर पर अभद्र इशारे किए और बाइक रोकने का प्रयास किया। शिवानी ने इसका विरोध करते हुए चालक को दूर रहने का संकेत दिया। इसके बाद कार ने अचानक ओवरटेक करते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी और मौके से निकल गई। टक्कर में शिवानी को चोटें आई हैं। उनके भाई दीपांकर के अनुसार, राइडिंग गियर पहने होने के बावजूद उनके घुटने में सूजन है। पीठ और गर्दन

की मांसपेशियों में खिंचाव तथा बाएं हाथ और दोनों हथेलियों पर खरोंच आई है। शिवानी का कहना है कि वह अभी भी घटना के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही हैं।

मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया बयान

मामले में शिवानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। पुलिस ने घटना के समय कार में सवार चार लोगों में से दो आरोपियों—कल्याण बैंसला और उसके चचेरे भाई—को गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

पिता बोले- बेटी अभी सदमे से नहीं उबरी

शिवानी के पिता रोशन चौहान ने कहा कि उनकी बेटी घटना के बाद से अभी पूरी तरह सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। उन्होंने बताया कि उन्हें मामले से जुड़ी जानकारी समाचार और सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। रोशन चौहान आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग से जुड़े हैं, जबकि शिवानी आम आदमी पार्टी की स्वयंसेवक और युवा विंग की सदस्य रह चुकी हैं।

शिवानी ने घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उनके पिता का कहना है कि घटना के बावजूद बेटी ने हिम्मत नहीं खोई है। परिवार का कहना है कि मामले में कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस घटना के वीडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार से जुड़े आरोपों की अंतिम स्थिति जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी।

तड़के सुबह पुलिस की दबिश, 6 संदिग्ध ठिकानों की तलाशी

बलौदाबाजार-भाटापारा। शहर में अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सिटी कोतवाली पुलिस ने मंगलवार तड़के विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीम ने भैंसापसरा, दशरमा रोड और इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में अचानक पहुंचकर कॉम्बिंग गश्त की। इस दौरान चिन्हित छह संदिग्ध मकानों और स्थानों पर दबिश देकर तलाशी ली गई। हालांकि जांच के दौरान किसी भी स्थान से संदिग्ध या अवैध सामग्री बरामद नहीं होने की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस के मुताबिक जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में 15 सितंबर 2026 को तड़के सिटी कोतवाली की विशेष टीम को शहर के संवेदनशील इलाकों में चेकिंग के लिए उतारा गया। टीम ने सबसे पहले भैंसापसरा, दशरमा रोड और इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त की। इन इलाकों में अलग-अलग जगहों पर संदिग्ध गतिविधियों की जांच की गई। अभियान के तहत पहले से चिन्हित मकानों और स्थानों की भी तलाशी ली गई। पुलिस के अनुसार इस विशेष अभियान का उद्देश्य अवैध रूप से देशी और अंग्रेजी शराब की बिक्री पर रोक लगाना, चोरी का सामान कबाड़ के रूप में खपाने जैसी गतिविधियों में शामिल संदिग्धों की पहचान करना और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखना था। अभियान के दौरान कुल छह संदिग्ध मकानों और स्थानों पर आकस्मिक दबिश दी गई। पुलिसकर्मियों ने इन स्थानों की गहन तलाशी लेने के साथ आसपास की गतिविधियों की भी जानकारी ली। हालांकि पूरे अभियान के दौरान किसी भी ठिकाने से अवैध शराब, संदिग्ध सामान या अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलने की जानकारी सामने नहीं आई। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियानों का उद्देश्य केवल अवैध सामग्री की बरामदगी नहीं, बल्कि संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाना और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाना भी है। शहर में कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए आने वाले दिनों में भी आकस्मिक चेकिंग और कॉम्बिंग गश्त जारी रखने की बात कही गई है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार के मार्गदर्शन में चलाया गया। सिटी कोतवाली की टीम ने सुबह के समय अलग-अलग इलाकों में पहुंचकर जांच की।

वाणिज्यिक कर निरीक्षक भर्ती परीक्षा बड़ी गड़बड़ियां मिलने के बाद रद्द

रायपुरः छत्तीसगढ़ के राज्य कर विभाग में लिपिक वर्ग से वाणिज्यिक कर निरीक्षक बनाने के लिए वर्ष 2022 में हुई सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में एक के बाद एक कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। जांच में चयनित अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं में एक जैसे जवाब मिलने, परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति रजिस्टर नहीं होने, परीक्षा का समेकित परिणाम और अंक सूची तैयार नहीं करने, उत्तरपुस्तिकाओं पर पहचान छिपाने के लिए कोड नहीं लगाने और कुछ अभ्यर्थियों के अंक दोबारा जांच में बढ़ाए जाने की बात सामने आई। इसके अलावा खरीदी गई और इस्तेमाल व बची हुई उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या में भी अंतर मिला। इन खामियों के बाद राज्य कर विभाग ने 26 जून 2022 को हुई पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है।

राज्य कर आयुक्त कार्यालय ने 11 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर परीक्षा और इसके आधार पर की गई पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही एक जुलाई 2022 को जारी वह आदेश भी रद्द कर दिया गया, जिसके जरिए चयनित कर्मचारियों को वाणिज्यिक कर निरीक्षक बनाया गया था। इस परीक्षा के आधार पर निरीक्षक बने सभी प्रभावित कर्मचारी अब अपने मूल पद पर वापस जाएंगे।

जांच में सामने आया कि परीक्षा से पहले आरक्षण रोस्टर के अनुसार अलग-अलग वर्ग के लिए पदों का बंटवारा नहीं किया गया था। विभाग के आदेश में कहा गया है कि इससे आरक्षण के नियमों का पालन प्रभावित हुआ और सभी पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर देने की व्यवस्था पर भी असर पड़ा।

»न्यूज खास

गांजा पीने से मना किया तो चापड़ से हमला युवक घायल

बिलासपुर. सिटी कोतवाली क्षेत्र के जूनीलाइन में रहने वाले आदित्य रजक ने बताया कि उसके पिता राजेंद्र रजक राकेश ज्वेलर्स में गार्ड का काम करते हैं. उनके मोहल्ले में सत्येंद्र यादव अक्सर गांजा पीता था. इस पर राजेंद्र ने आपत्ति जताते हुए इसकी शिकायत की थी. इसी बात को लेकर सत्येंद्र राजेंद्र से नाराज था. रविवार रात करीब आठ बजे सत्येंद्र यादव राजेंद्र और आदित्य के घर के पास पहुंचा, लेकिन दोनों वहां नहीं मिले. इसके बाद वह सदर बाजार के करोना चौक स्थित राकेश ज्वेलर्स पहुंच गया. आरोपी दुकान के अंदर घुसा और वहां ड्यूटी कर रहे राजेंद्र पर चापड़ से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से राजेंद्र गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. घटना के दौरान दुकान में मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ने का प्रयास किया और किसी तरह उसे काबू में कर लिया.

युवक ने खुद के पैरों में बांधी पत्थर से भरी बोरी, फिर कुएं में लगा दी छलांग

सूरजपुर। सूरजपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने आत्महत्या कर लिया है। युवक ने आत्महत्या के लिए जो तरीका अपनाया है वो हैरान कर देने वाला है। उसने पहले पत्थरों से भरे बोरे को रस्सी से अपने पैरों में बांध लिया और फिर कुएं में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान कल्याणपुर गांव निवासी सुमेर सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुमेर पहले भी दो बार अपनी जान देनी की कोशिश कर चुका था। एक बार उसने फांसी लगाने का प्रयास किया था, लेकिन पेड़ का डंगाल टूटने कि वजह से वह बच गया था। दूसरी बार उसने कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन तैरने आने की वजह से वह बच गया था। सुमेर ने इस बार बड़े प्लानिंग से पैरों को रस्सी और पत्थर से बांधकर कुएं में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बताया कि सुमेर सनकी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसकी गांव के लोगों से नहीं बनती थी। फिलहाल पुलिस ने मामले कि जांच में जुटी हुई है।

मेन रोड के पास पेड़ से लटका मिला शव, इलाके में फैली सनसनी

कोरबा। जिले के छुरीकला निवासी नवप्रसूता कविता केंवट का शव मंगलवार दोपहर ग्राम जेंजरा मेन रोड के पास पेड़ से फंदे पर लटका मिला। कविता को 10 सितंबर को प्रसव के लिए जेंजरा स्थित जीवांश अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार, प्रसव के बाद कविता के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद नवजात को अस्पताल के स्ह्रष्ट/ढ्ढष्ट में रखा गया था। बताया जा रहा है कि बीती रात किसी बात को लेकर कविता अपने परिजनों से नाराज हो गई और अचानक अस्पताल से बाहर निकल गई। कविता के अस्पताल से चले जाने के बाद परिजनों ने रातभर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे ग्राम जेंजरा मेन रोड के पास ग्रामीणों की नजर पेड़ से लटके शव पर पड़ी। इसकी सूचना सरपंच को दी गई, जिसके बाद सरपंच ने कटघोरा पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के पीछे की वास्तविक वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस परिजनों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ कर मामले की परिस्थितियों की जांच कर रही है।

आशीर्वाद का दीया जलाकर पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना

आज जिलेभर में होगा आशीर्वाद का दीप कार्यक्रम

रायपुर। सेवा, समर्पण, सुशासन और जनभागीदारी की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 17 सितंबर को आयोजित 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों में भी उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनकी 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा को समर्पित इस अभियान को जिलेभर में व्यापक जनभागीदारी के साथ आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। भाजपा रायपुर जिला ग्रामीण के मंत्री आशीर्वाद का दीया अभियान जिला सह प्रभारी विकास कोटवानी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल दीप जलाना नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों के आशीर्वाद, शुभकामना और जनभागीदारी की भावना को एक साथ जोड़ना है। उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहर तक भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और इस आयोजन को जन-अभियान का स्वरूप देने में जुटे हैं। कोटवानी ने कहा कि कल 17 सितंबर को हर घर में एक दीया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के साथ जलाया जाए, यही इस अभियान का मूल भाव है। उन्होंने बताया कि वे आरंग, मंदिर हसौद, खरोरा, धरसीवा और तिल्दा सहित रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों से संपर्क कर उन्हें अभियान में सहभागी बनने का आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। कई लोग स्वयं आगे आकर प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन किसी एक व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि जनभागीदारी के माध्यम से सेवा और सुशासन की भावना को मजबूत करने का अवसर है। विकास कोटवानी ने कहा, ₹यह दीया सिर्फ एक दीया नहीं होगा, बल्कि उन करोड़ों परिवारों की उम्मीद, विश्वास और आशीर्वाद का प्रतीक होगा, जिन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। जब किसी गरीब परिवार को पक्का मकान मिलता है, जब किसी परिवार को सम्मान और सुरक्षा का एहसास होता है, तो उसके जीवन में आया यह बदलाव भी इस दीप के उजाले का हिस्सा है। 17 सितंबर को हम इसी विश्वास और आशीर्वाद को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों से संवाद भी किया जाएगा। लाभार्थी अपने अनुभव साझा करेंगे कि पक्का मकान मिलने के बाद उनके जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व किस तरह बढ़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित योजनाओं से लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और इन परिवारों की भागीदारी इस अभियान को और सार्थक बनाएगी। भाजपा रायपुर जिला ग्रामीण अध्यक्ष श्याम नारंग भी पुरे जिले में कार्यक्रम की तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भाजपा रायपुर जिले के दोनों महामंत्री उपाध्यक्ष शिव शंकर वर्मा जिला कोषाध्यक्ष एवं तिल्दा भाजपा के प्रभारी अरविंद ठाकुर के अलावा भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक महेश अग्रवाल, नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के जिला सह प्रभारी लख्मीचंद नागवानी तथा भाजपा के वरिष्ठ युवा नेता दीपक शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं।

विकास कोटवानी ने बताया तिल्दा में 25 हजार से अधिक दिया रोशन होगे जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रत्येक परिवार अपने घर में 'आशीर्वाद का दीप' जलाकर इस जन-अभियान में सहभागी बने। उन्होंने कहा कि जब हजारों-लाखों घरों में एक साथ दीप जलेगा तो यह सेवा, सुशासन और जनभागीदारी के संकल्प का संदेश पूरे समाज तक पहुंचेगा

सामुदायिक शौचालय में खुल गई चाय-नाश्ते और अंडे की दुकान

प्रतापपुर में सरकारी योजना का अनोखा हाल, शौचालय पर कब्जे का आरोप; सरपंच-सचिव की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

प्रतापपुर। विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत घाट पेंडारी से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और पंचायत की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सड़क किनारे बनाए गए सामुदायिक शौचालय को ही रूप से दुकान में तब्दील कर दिया गया है। शौचालय में चाय-नाश्ता, बीड़ी-सिगरेट और अंडे की दुकान का संचालन किए जाने की बात सामने आई है। ग्रामीणों के मुताबिक पंचायत द्वारा आम लोगों की सुविधा और स्वच्छता के उद्देश्य से निर्मित सामुदायिक शौचालय पर लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा कर दुकान संचालित की जा रही है। दुकान को बाकायदा व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है, जिससे सरकारी संपत्ति के उपयोग और पंचायत की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस स्थान का निर्माण लोगों को स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था, उसी को अब चाय-नाश्ता और अंडे की दुकान संचालित होने की चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी जमकर चर्चा हो रही है और लोग इसे लेकर तरह-तरह का प्रांताक्रयाए द रह हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत स्तर पर सरकारी संपत्ति की उचित निगरानी नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। इससे केंद्र सरकार की स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर भी सवाल उठ रहे हैं। वही आम जनता के सुविधा के लिए बनाए गए शौचालय में इस तरह का अमला सामने आने के बाद में हास्य रूप दिया जा रहा है। और ज्यादा शासन प्रशासन की कीर कीरो भी हो रही है।

शौचालय बना दुकान, निगरानी व्यवस्था पर सवाल

लोगों का कहना है कि यदि सरकारी भवन और सामुदायिक शौचालयों की नियमित निगरानी होती तो इस तरह वहां लंबे समय तक दुकान का संचालन संभव नहीं होता। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर शौचालय को कब्जे से मुक्त कराने तथा जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनपद पंचायत और संबंधित विभाग के अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और सरकारी शौचालय को दुकान में तब्दील करने की अनुमति आखिर किस स्तर से मिली।

"इस विषय में जनपद पंचायत सीईओ अनिल तिवारी ने कहा कि मामले की जांच कराकर कारवाही की जाएगी

स्वाइन फ्लू से मौत की पुष्टि

जांजगीर-चांपा. पिछले दिनों स्वाइन फ्लू के लक्षणों से मृत व्यक्ति की सैम्पल जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू से मौत की पुष्टि हो गई है. उधर रायपुर से बालपुर अपने ससुराल घूमने आये एक युवक की स्वाइन फ्लू जांच रिपोर्ट पाजिटिव आई है. युवक की कांटेक्ट हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है. बता दें कि 6 से ज्यादा संदिग्ध मरीज स्वाइन फ्लू के मिले हैं. इनमे से ज्यादातर को प्रायमरी उपचार के बाद हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय दो मरीज भर्ती है. जिनका जांच के लिए सैम्पल लेकर भेजा गया था लेकिन दोनो का जांच रिपोर्ट निगेटिव आया है. दूसरा मामला चांपा के एक निजी अस्पताल का है. जहां सर्दी खांसी के इलाज के लिए एक युवक आया था. 12 सितम्बर को उक्त युवक की स्वाइन फ्लू की जांच के लिए सैम्पल भेजा गया था. शनिवार 13 सितम्बर को उक्त युवक की जांच रिपोर्ट पाजिटिव आई है. बताया जा रहा है कि युवक रायपुर से बालपुर अपने ससुराल आया था. जिसे सर्दी-खांसी होने पर वह चांपा के निजी अस्पताल में इलाज के लिए गया, जहां युवक सिम्टोमेटिक होने के कारण सैम्पल जांच के लिए भेजा गया. इसके अलावा जिला चिकित्सालय में 2 को आईसोलेशन पर रखा गया है.

गणेश प्रतिमा खरीदने आए युवक से मारपीट कर लूट, दो आरोपी गिरफ्तार

धमतरी। गणेश प्रतिमा खरीदने धमतरी आए युवक को रास्ते में रोककर मारपीट और लूटपाट करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए दस्तावेज, नकदी रकम और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व स्कूटी जब्त की गई है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में की गई। पुलिस के अनुसार, ग्राम बोरिदकला, थाना पुरुर, जिला बालोद निवासी रोहित कुमार यादव (24) अपने साथियों के साथ 14 सितंबर को मोटरसाइकिल से गणेश प्रतिमा खरीदने धमतरी के कुम्हारपारा आ रहा था। दोपहर करीब 2 बजे रिसाईपारा म्युनिसिपल स्कूल के पास दो दोपहिया वाहनों में सवार युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद रोहित का पर्स लूटकर फरार हो गए। पर्स में 10 हजार रुपये नकद के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस तथा बैंक ऑफ बड़ौदा और ग्रामीण बैंक के एटीएम कार्ड रखे थे। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। प्रार्थी के बताए हुलिए, घटनास्थल से मिले सुराग और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रिसाईपारा क्षेत्र में दबिश देकर दो संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ और विवेचना में संलिप्तता सामने आने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजवीर सिंह उर्फ गिन्नी मेहरा (20), निवासी रिसाईपारा, धमतरी और राहुल उर्फ रोहित सोना (26), निवासी जालमपुर वार्ड, स्वीपर कॉलोनी, धमतरी के रूप में हुई है। पुलिस ने राजवीर के कब्जे से 1,000 रुपये नकद, प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, दो एटीएम कार्ड और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्रमांक CG 05 AP 8201 बरामद की है। वहीं राहुल के कब्जे से 1,000 रुपये नकद और वारदात में प्रयुक्त सुजुकी एक्सेस स्कूटी क्रमांक CG 05 AV 0124 जब्त की गई है। थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 221/2026 के तहत धारा 296, 306(5), 3(5) बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

बिना चर्चा और पर्याप्त जानकारी के एजेंडा तय करने का आरोप, पार्षदों ने मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

प्रतापपुर नपं की परिषद बैठक के एजेंडे पर कांग्रेस पार्षदों का बड़ा विरोध

वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद मासूम इराकी ने उठाया सवाल

वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद मासूम इराकी ने कहा कि नगर पंचायत के महत्वपूर्ण निर्णयों और कार्यों में कांग्रेस पार्षदों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्षद जनता के बीच से चुनकर आते हैं, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले उन्हें विश्वास में लेकर उनकी राय और सुझाव लिए जाने चाहिए।

सूरजपुर। जिला के नपं प्रतापपुर में प्रस्तावित परिषद की बैठक को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने पहली बार सामूहिक रूप से विरोध दर्ज कराते हुए मुख्य नपं अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि परिषद की बैठक में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण विषयों और एजेंडे को लेकर कांग्रेस के निर्वाचित पार्षदों से पर्याप्त चर्चा नहीं की गई तथा उन्हें समय पर आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि परिषद की बैठक नगर पंचायत के विकास कार्यों और महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रमुख मंच है। ऐसे में बैठक में रखे जाने वाले विषयों पर सभी निर्वाचित पार्षदों को जानकारी देना और उनके सुझाव लेना आवश्यक है। पार्षदों ने बिना पर्याप्त चर्चा एवं जानकारी के एजेंडा निर्धारित कर परिषद की बैठक आयोजित किए जाने की प्रक्रिया पर सामूहिक आपत्ति जताई है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि बैठक के सभी विषयों एवं एजेंडे की जानकारी पार्षदों को समय पूर्व दी जाए, महत्वपूर्ण विषयों पर सभी पार्षदों से चर्चा एवं सुझाव लिए जाएं तथा परिषद की कार्यवाही में सभी निर्वाचित पार्षदों की सहभागिता और सम्मान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही नियम विरुद्ध कार्यों के स्थल परिवर्तन जैसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं होने देने की मांग भी रखी गई है। पार्षदों का कहना है कि उनका विरोध किसी विकास कार्य को रोकने के लिए नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है। जनता ने चुनकर भेजा, फिर निर्णय में हमारी बात क्यों नहीं? उन्होंने स्पष्ट कहा कि विरोध विकास कार्यों का नहीं, बल्कि पार्षदों को निर्णय प्रक्रिया में उचित महत्व नहीं दिए जाने का है।एक माह से स्ट्रीट लाइट बंद, कांग्रेस वार्डों की अनदेखी क्यों वार्ड क्रमांक 10 की पार्षद प्रियंकल तिवारी ने मूलभूत सुविधाओं पर उठाए सवाल वार्ड क्रमांक 10 की पार्षद प्रियंकल तिवारी ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड की मुख्य सड़क की स्ट्रीट लाइट करीब एक माह से खराब है। इसके अलावा सफाई, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के मामले में भी वार्ड की अपेक्षित देखरेख नहीं हो रही है।

उन्होंने कहा कि वार्ड की समस्याओं को लेकर पार्षद और जनता दोनों परेशान हैं, फिर भी समय पर समाधान नहीं हो रहा। प्रियंकल तिवारी ने स्ट्रीट लाइट सहित मूलभूत सुविधाओं को तत्काल दुरुस्त कराने की मांग की है।

अब प्रशासन के जवाब पर नजर

कांग्रेस पार्षदों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के बाद नगर पंचायत की कार्यप्रणाली और परिषद बैठक की प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

एक तरफ पार्षदों ने एजेंडे को लेकर पारदर्शिता और सहभागिता की मांग उठाई है, वहीं दूसरी ओर वार्ड स्तर पर स्ट्रीट लाइट, सफाई और बिजली जैसी समस्याओं को भी सामने रखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि नगर पंचायत प्रशासन कांग्रेस पार्षदों की आपत्तियों और वार्डों की समस्याओं पर क्या कार्रवाई करता है और आगामी परिषद बैठक में इन मुद्दों पर क्या स्थिति सामने आती है।

छत काटकर शो-रूम में घुसे चोर, कैश के साथ डीवीआर भी ले गए

पेंड्रा। अडभार रोड स्थित एक शो-रूम में अज्ञात चोरों ने छत काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर शो-रूम के अंदर दाखिल हुए और काउंटर की दराज का ताला तोड़कर करीब 30 हजार रुपये नगद ले गए। इसके साथ ही वहां लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी चोरी कर लिया गया। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 45 हजार रुपये बताई गई है। शिकायत मिलने के बाद पेंड्रा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना पेंड्रा थाना क्षेत्र के अडभार रोड की है। वार्ड नंबर 11 निवासी नवीन फरमानिया अपने पिता नरेश कुमार फरमानिया के साथ यहां %नवीन ट्रेडर्स% नाम से शो-रूम संचालित करते हैं। नवीन के मुताबिक रोज की तरह रात करीब 8 बजे काम खत्म होने के बाद शो-रूम बंद कर वे घर चले गए थे। अगले दिन सुबह करीब 8:30 बजे नरेश कुमार फरमानिया अपने कर्मचारी सागर प्रजापति के साथ शो-रूम खोलने पहुंचे। दरवाजा खोलकर अंदर जाने पर उन्हें सामान अस्त-व्यस्त दिखाई दिया। काउंटर की दराज खुली हुई थी और उसका ताला भी टूटा मिला। स्थिति देखकर उन्हें चोरी की आशंका हुई। काउंटर की जांच करने पर दराज में रखे करीब 30 हजार रुपये गायब मिले। इसके बाद शो-रूम संचालक ने घटना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश की, लेकिन वहां लगा डीवीआर भी गायब मिला।

भारत का एशिया कप में अभूतपूर्व दबदबा

पुरुष और महिला टीमों ने मिलकर जीती 17 ट्रॉफियां

नई दिल्ली। एशिया कप क्रिकेट टूनार्मेंट में भारतीय क्रिकेट का दबादबा सिर्फ पुरुष टीम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महिला टीम ने भी लगातार शानदार प्रदर्शन कर इसे और मजबूत किया है।

हाल ही में 2026 में आठवीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम करने के बाद, अगर पुरुष और महिला दोनों टीमों के एशिया कप खिताबों को एक साथ जोड़ा जाए, तो भारत के नाम कुल 17 ट्रॉफियां हो चुकी हैं। यह आंकड़ा बाकी सभी टीमों से काफी आगे निकल गया है और भारतीय क्रिकेट की शक्ति को दशार्ता है। पुरुष एशिया कप की बात करें तो भारत इस टूनार्मेंट का सबसे सफल देश है। भारतीय पुरुष टीम ने अब तक 9 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जिसमें वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट की जीत शामिल हैं। श्रीलंका 6 खिताब के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान ने अब तक 2 बार यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती है।

महिला क्रिकेट में भी भारत का रिकॉर्ड बेहद मजबूत है। 2026 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर आठवीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। इस शानदार जीत के साथ भारत ने अपने महिला एशिया कप खिताबों की संख्या 8 कर ली। महिला एशिया कप में भारत के बाद श्रीलंका और बांग्लादेश का नंबर आता है, जिन्होंने 1-1 बार यह खिताब जीता है। दोनों टीमों के प्रदर्शन को मिलाकर देखें तो, भारत के पास कुल 17 एशिया कप ट्रॉफी हैं। श्रीलंका के पास पुरुषों की 6 और महिलाओं की 1, यानी कुल 7 ट्रॉफी हैं, जिससे वह दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तान ने पुरुषों में 2 बार खिताब जीता है, जबकि महिला टीम के नाम एशिया कप ट्रॉफी नहीं है, इसलिए उसका कुल आंकड़ा 2 ट्रॉफी का है। बांग्लादेश के पास महिला एशिया कप की 1 ट्रॉफी है। इस प्रकार, भारत 17 ट्रॉफी के साथ तालिका में शीर्ष पर है, जो उसकी क्षेत्रीय क्रिकेट में अद्वितीय श्रेष्ठता को दशार्ता है।

दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक, तोड़ना है बेहद मुश्किल

नई दिल्ली। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड आज भी एक ऐसे बल्लेबाज के नाम दर्ज है, जिसे तोड़ना वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जैसे विस्फोटक खिलाड़ियों के लिए भी बेहद मुश्किल साबित हो सकता है।

यह रिकॉर्ड नेपाल के धुरंधर खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम है, जिन्होंने 27 सितंबर, 2023 को मंगोलिया के खिलाफ सिर्फ 9 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इतिहास रचा था। वह दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 10 या इससे कम गेंदों में फिफ्टी पूरी की है। उस मैच को नेपाल ने 273 रनों के विशाल अंतर से जीता था, जहां दीपेंद्र की यह पारी एक महत्वपूर्ण आकर्षण रही थी। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह हैं, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में अर्धशतक लगाया था, जो लंबे समय तक एक विश्व रिकॉर्ड रहा था। उनके अलावा, ऑस्ट्रिया के अबदुल्लाह कोटवा भी 12 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इस खास क्लब में शामिल हैं।

हाल के समय में, भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए क्रिकेट जगत में मशहूर हुए हैं। उन्होंने इसी साल जिम्बाब्वे दौरे पर 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था, जो उनका टी20 इंटरनेशनल में अब तक का सबसे तेज अर्धशतक है। हालांकि, उन्हें अभी गिनती के मैच खेले हैं और उनसे भविष्य में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है। वैभव अभी टीम इंडिया के साथ दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा हैं, हालांकि उन्हें पहले मैच में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल पाई थी। वहीं, अभिषेक शर्मा ने भी इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 गेंदों में फिफ्टी जड़कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था और वह संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। इन युवा प्रतिभाओं के बावजूद, दीपेंद्र सिंह ऐरी का 9 गेंदों में अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ना वास्तव में एक असाधारण चुनौती होगी।

कप्तान पैट कमिंस को मुश्किलों का अनुमान

सैंडपेपर गेट विवाद के बाद दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया की पहली टेस्ट सीरीज

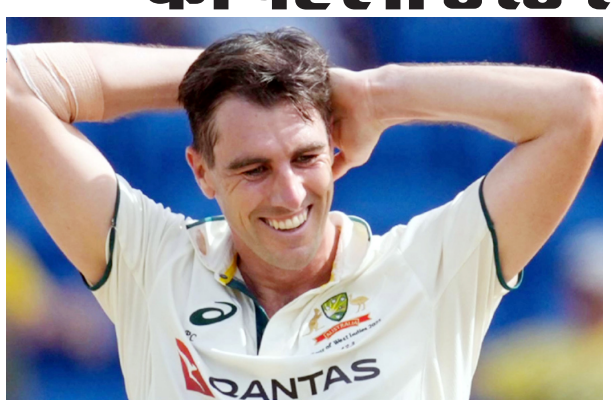

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा 24 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें तीन वनडे और तीन टेस्ट मैच खेले जाएंगे। यह दौरा 2018 के बहुचर्चित सैंडपेपर गेट विवाद के बाद ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण अफ्रीका में पहला टेस्ट सीरीज दौरा है। इस पृष्ठभूमि में, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का मानना है कि इस दौरे पर उनकी टीम को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कमिंस ने कीपिन इट क्रिकेट पॉडकास्ट के दौरान कहा, टेस्ट सीरीज के दौरान थोड़ी दुश्मनी हो सकती है। लेकिन यह एशेज सीरीज से ज्यादा शोरगुल वाला नहीं हो सकता, जैसे बर्मिंघम के एजबेस्टन का हॉलीज स्टैंड बहुत शोरगुल वाला हो जाता है।

दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट खेलने के अपने अनुभव पर पैट कमिंस ने कहा कि दर्शक दीर्घा के कुछ हिस्से अक्सर उग्र हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने यह सब पहले भी देखा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि एक कप्तान के तौर पर वह मैदान के बीच में रहेंगे और सीधे दर्शकों के संपर्क में नहीं आएंगे। कमिंस ने विश्वास व्यक्त किया कि अब तक वह विवाद शांत हो गया होगा और उनकी टीम का पूरा ध्यान क्रिकेट पर रहेगा। उन्होंने कहा, हर कोई आगे बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि तीन टेस्ट मैचों में, आप क्रिकेट में पूरी तरह से फंस जाते हैं, और हर कोई बहुत जल्दी क्रिकेट के बारे में चिंता करने लगता है। मुझे यकीन है कि भीड़ में कुछ गुस्सैल लोग होंगे, और कुछ लेख या मीडिया में ऐसी बातें सामने आएंगी, लेकिन हमारा समूह आगे बढ़ गया है।

2018 में हुए बॉल-टैम्परिंग (गेंद से छेड़छाड़) के मुद्दे ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को गंभीर संकट में डाल दिया था, जिसके बाद स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर एक साल का और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर नौ महीने का प्रतिबंध लगा था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही टीमों के लिए यह सीरीज बेहद अहम है। यह टेस्ट सीरीज अपने ऐतिहासिक संदर्भ और दोनों टीमों की मौजूदा स्थिति के कारण बेहद रोमांचक होने वाली है और दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों की इस पर खास नजर रहेगी।

30 की उम्र में गजब की फिट, जानें स्मृति मंधाना का फिटनेस रूटीन

नॉनवेज नहीं खातीं स्मृति

नई दिल्ली। भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की उप-कप्तान और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना न केवल अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनकी लाजवाब फिटनेस भी हमेशा चर्चा में रहती है। महज 30 साल की उम्र में अपनी गजब की फिटनेस के पीछे कोई जटिल डाइट या

अत्यधिक मेहनत नहीं, बल्कि एक अनुशासित और सरल रूटीन है। स्मृति मंधाना घर का बना सिंपल खाना पसंद करती हैं और वह पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं, खासकर लैक्टो-ओवो-वेजिटेरियन डाइट फॉलो करती हैं, जिसमें अनाज, फल, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडा शामिल होते हैं, लेकिन मीट-चिकन से दूरी बनाए रखती हैं। प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए वह प्रोटीन शेक और अंडे का सेवन करती हैं, साथ ही खुद को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी और नारियल पानी भी पीती हैं।

स्मृति का मानना है कि शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए वर्कआउट में विविधता बेहद जरूरी है। वह हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करती हैं, जिसमें हर दिन कुछ अलग सेशन शामिल होता है। पैरों की मजबूती के लिए वह रोजाना रनिंग करती हैं और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, लंजेस और पुल-अप्स जैसे व्यायाम करती हैं। वह अनुशासन के साथ वर्कआउट करती हैं और कभी एक भी दिन स्किप नहीं करतीं। अगर सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को जिम जाती हैं।

अपनी डाइट में सख्ती बरतने के बावजूद, स्मृति की कुछ कमजोरियां भी हैं। उन्हें मारवाड़ी खाना और भेलपूरी बहुत पसंद है, जिसका स्वाद वह कभी-कभार चीट डे पर लेती हैं। मीठे से वह सख्त दूरी बनाकर रखती हैं, लेकिन अगर क्रेविंग होती है तो सेहतमंद डार्क चॉकलेट का विकल्प चुनती हैं। स्मृति मंधाना का फिटनेस मंत्र बेहद सीधा है: फिट रहने के लिए खुद को रूटीन और तय समय के साथ अनुशासित करना होगा। उनका मानना है कि एक दिन छोड़कर एक दिन वर्कआउट करने से कभी भी फिट नहीं रहा जा सकता, और एक संतुलित आहार फिटनेस का सबसे अहम हिस्सा है, जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए।

एशियन गेम्स से बाहर होने के बाद ड्रेसाज चैंपियन अनुष अग्रवाला का छलका दर्द

नई दिल्ली। भारत के ड्रेसाज राइडर और 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स के ऐतिहासिक गोल्ड मेडलिस्ट अनुष अग्रवाला ने 2026 एशियन गेम्स के लिए चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। टीम में जगह नहीं मिलने के बाद 25 वर्षीय अनुष ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए इसे खेल में मिली हार के बजाय विश्वासघात जैसा बताया है। अनुष, जिन्होंने 2022 में टीम गोल्ड और व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2024 पेरिस ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है, अब आगामी एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अनुष को जून में इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया (ईएमआई) की एडहॉक कमेटी द्वारा पहली रिजर्व खिलाड़ी के रूप में चुना गया था, लेकिन अंतिम चार सदस्यीय टीम में उन्हें जगह नहीं मिली। इस पर उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक करते हुए कहा, मैं इसलिए गहराई से आहत हूं क्योंकि मैं प्रतियोगिता में हारा नहीं, बल्कि मुझे प्रतियोगिता करने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि यह हार से कम और विश्वासघात जैसा ज्यादा महसूस हो रहा है। उनका मानना है कि वह मैदान पर हार स्वीकार कर सकते हैं, पर बिना मौका मिले बाहर होना कष्टप्रद है। जर्मनी में लंबे समय तक ट्रेनिंग करने वाले अनुष ने इस चयन के खिलाफ साथी रिजर्व खिलाड़ी सुदीप्ति हजेला के साथ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख भी किया था। हालांकि, अदालत ने उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया निर्धारित मानदंडों के अनुसार हुई थी और इसमें मनमानी या पक्षपात नहीं मिला।

कारोबार

लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ खुला शेयर बाजार, एफएमसीजी स्टॉक्स में खरीदारी

मुम्बई। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में मजबूती के साथ खुला. सेंसेक्स 242.54 अंक या 0.33 प्रतिशत की मजबूती के साथ 74,246.36 और निफ्टी 83 अंक या 0.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,201.60 पर था.

एफएमसीजी स्टॉक्स में जबरदस्त खरीदारी

शुरूआती कारोबार में तेजी का नेतृत्व एफएमसीजी स्टॉक्स कर रहे थे. सूचकांकों में निफ्टी एफएमसीजी एक प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ टॉप गेनर था. इसके अलावा, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑटो, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी कमोडिटीज और निफ्टी आईटी के साथ ज्यादातर सूचकांक हरे निशान में थे. केवल निफ्टी इंडिया डिफेंस ही लाल निशान में था.

मिडकैप और स्मॉलकैप में मिलाजुला कारोबार

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में मिलाजुला कारोबार हो रहा था. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 95 अंक या 0.16 प्रतिशत की मजबूती के साथ 60,975 और निफ्टी स्मॉलकैप 5 अंक या 0.03 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 19,416 पर था. सूचकांकों में आईटीसी, एमएंडएम, बीईएल, एसबीआई, एचयूएल, एचसीएल टेक, एसबीआई, एशियन पेंट्स, अदाणी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, ट्रेंट, टाइटन, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस गेनर्स थे. वहीं, एनटीपीसी, इंडिगो, एचडीएफसी बैंक और इटरनल लूजर्स थे.

एशियाई बाजारों में भी आज तेजी

ज्यादातर एशियाई बाजार हरे निशान में थे. टोक्यो, शंघाई, सोल और जकार्ता में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था. वहीं, हांगकांग और बैंकॉक लाल निशान में थे. अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.63 प्रतिशत की कमजोरी के साथ और टेक्नोलॉजी इंडेक्स नैस्डैक 0.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ.

जानकारों ने कहा कि यूएस बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं. जब तक ये दोनों अहम मैक्रो-इकोनॉमिक फैक्टर प्रतिकूल बने रहेंगे, तब तक बाजार में बड़ी रिकवरी की उम्मीद करना सही नहीं होगा. पिछले 5 दिनों से एफआईआई बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और यूएस 10-साल के बॉन्ड यील्ड के 5 प्रतिशत पर होने के कारण, बाजार में आने वाली हर छोटी तेजी पर उनके बिकवाली करने की संभावना है.

क्या फ्री यूपीआई का दौर अब खत्म हुआ?

नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान की दुनिया में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने साफ कर दिया है कि सरकार 15 अक्तूबर से चुनिंदा व्यापारी भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने जा रही है। एमडीआर वह शुल्क है जो दुकानदारों या व्यापारियों से डिजिटल भुगतान (जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई) स्वीकार करने के बदले बैंक या पेमेंट प्रोसेसर की ओर से वसूला जाएगा। हालांकि, आम लोगों से किसी भी लेनदेन के बदले कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वे पहले की तरह की इसका मुफ्त इस्तेमाल कर पाएंगे।

एमडीआर का नया नियम

यह शुल्क हर आम आदमी या हर लेनदेन पर नहीं लगेगा। यूपीआई के जरिये होने वाले कुल मर्चेंट ट्रांजैक्शन का 95 फीसदी हिस्सा 2,000 रुपये से कम का होता है। इन सभी छोटे भुगतानों पर एमडीआर पूरी तरह शून्य रहेगा। जो ग्राहक या व्यापारी 2,000 रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं, उन पर मानक रूप से 0.4% का एमडीआर तय किया गया है। यदि भुगतान 75,000 रुपये या उससे अधिक का है, तो शुल्क को अधिकतम 300 पर सीमित रखा गया है।

- रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन जैसे क्षेत्रों के लिए 2,000 रुपये से ऊपर के लेन-देन पर 5 रुपये का फ्लैट एमडीआर रखा गया है।
- म्यूचुअल फंड और स्टॉकब्रोकर जैसे कैपिटल-मार्केट भुगतानों पर यह दर मात्र 0.02% (अधिकतम 300 रुपये तक) होगी।
- यूपीआई से प्रति माह 1 लाख रुपये तक पाने वाले छोटे विक्रेता पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।

आईएमफ ने की भारत की आर्थिक बढ़ोतरी की तारीफ, कहा- भारत के पास नेतृत्व करने की क्षमता

नई दिल्ली। भारत की पांच दविसीय यात्रा पूरी करने के बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के उप-प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को लेकर बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया की आर्थिक बढ़ोतरी की अगली बड़ी लहर का नेतृत्व करने की क्षमता है. इसकी वजह देश की मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की तेज प्रगति और लगातार बढ़ती तकनीकी क्षमताएं हैं.

भारत आने पर जताई खुशी

उन्होंने कहा, आईएमएफ के उप-प्रबंध निदेशक के रूप में पहली बार भारत आकर मुझे बहुत खुशी हुई. नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग जगत के नेताओं और अन्य लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला. क्लार्क ने निर्मला सीतारमण, संजय मल्होत्रा और अशोक कुमार लाहिड़ी को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत और सकारात्मक चचाओं के लिए धन्यवाद दिया. आईएमएफ अधिकारी ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, मजबूत आर्थिक आधार और अच्छी नीतियों की वजह से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और वैश्विक विकास का एक प्रमुख इंजन है.

दिल्ली-मुंबई में अहम बैठकों में लिया हिस्सा

भारत की यात्रा के दौरान इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया. वॉशिंगटन से जारी एक बयान में क्लार्क ने कहा, ₹भारत दुनिया की अगली आर्थिक वृद्धि को गति देने की क्षमता रखता है और आईएमएफ इस सफर में देश

का करीबी साझेदार बना रहेगा.₹ आईएमएफ में उप-प्रबंध निदेशक बनने के बाद यह क्लार्क की भारत की पहली यात्रा थी. उन्होंने वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की.

'जोखिमों के बीच आर्थिक स्थिरता और मजबूती बनाए रखना जरूरी'

क्लार्क ने बताया कि भारतीय नीति-निमार्ताओं के साथ उनकी बातचीत में देश की आर्थिक स्थिति, वैश्विक परिस्थितियों में हो रहे बदलाव और टिकाऊ तथा सबको साथ लेकर चलने वाली आर्थिक वृद्धि के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा, ₹दुनिया में बढ़ती अनिश्चितताओं और बदलते जोखिमों के बीच आर्थिक स्थिरता और मजबूती बनाए रखना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि हमने इस बात पर चर्चा की कि नीतियां परिस्थितियों के अनुसार लचीली बनी रहें, महंगाई नियंत्रण में रहे और ऐसे सुधार आगे बढ़ाए जाएं जो उत्पादकता बढ़ाएं, प्रतिस्पर्धा मजबूत करें और मध्यम अवधि में तेज विकास को बनाए रखें. क्लार्क ने भारत सरकार को बहुपक्षीय सहयोग को समर्थन देने और क्षेत्र के अन्य देशों की मदद करने के लिए भी धन्यवाद दिया.

उद्योगपतियों और कारोबारी नेताओं से की मुलाकात

यात्रा के दौरान उन्होंने कई उद्योगपतियों और कारोबारी नेताओं से मुलाकात की और यह समझने की कोशिश की कि भारत का निजी क्षेत्र देश की आर्थिक प्रगति में किस तरह योगदान दे रहा है. उन्होंने कहा कि मुझे व्यापार जगत के नेताओं से बातचीत का अवसर मिला और मैं भारत के निजी क्षेत्र की ऊर्जा, यहां मौजूद प्रतिभाशाली लोगों और तेजी से विकसित हो रही तकनीकी तथा मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं से काफी प्रभावित हुआ. क्लार्क के अनुसार, नवाचार (इनोवेशन), डिजिटल बदलाव, उन्नत विनिर्माण और नई तकनीकों को अपनाना ऐसे बड़े कारक हैं जो उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमारी चचाओं से यह स्पष्ट हुआ कि नवाचार, डिजिटल परिवर्तन, उन्नत विनिर्माण और तकनीक का व्यापक उपयोग उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, प्रतिस्पर्धा को मजबूत कर सकते हैं और अधिक मूल्य वाले आर्थिक कार्यों को बढ़ावा दे सकते हैं.

धार जिले के राजोद में कचरे की दुर्गंध से स्कूल की 6 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, तीन अस्पताल में भर्ती

राजोद, धार। कन्या हायर सेकंडरी स्कूल राजोद में गुरुवार को कचरे की दुर्गंध के कारण करीब 5-6 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया।

छात्राओं को घबराहट होने के साथ मचलने की शिकायत हुई। उन्होंने इसकी जानकारी अपने क्लास टीचर और प्राचार्य जेके शर्मा को दी। इसके बाद प्राचार्य छात्राओं को तत्काल राजोद अस्पताल लेकर पहुंचे।

अस्पताल में डॉक्टर भंवर ने छात्राओं का उपचार किया। तीन छात्राओं को इंजेक्शन और गोलियां देकर अस्पताल में भर्ती किया गया। इनमें दिव्या जाट निवासी सदला, राधा चरण निवासी रानीखेड़ी राजोद और अंगूरबाला निवासी झिंझोटा की तबीयत अधिक खराब बताई गई। अधिक तकलीफ होने पर इन्हें सरदारपुर रेफर करने की बात कही गई।

स्कूल के पास पूरे राजोद का कचरा एकत्रित किया जाता है। यहां कचरा जमा होने से लगातार दुर्गंध की समस्या बनी रहती है। स्कूल प्रबंधन के अनुसार, दुर्गंध के कारण पहले भी कई बार छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस समस्या की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी दी जा चुकी है।

प्राचार्य जेके शर्मा द्वारा सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल को भी समस्या से अवगत कराने की बात कही गई है। आरोप है कि कचरा हटाने का आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। परीक्षा के समय छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में चिंता है।

समय रहते समस्या हल करने की मांग

स्कूल प्रबंधन का कहना है कि यदि कचरे का ढेर जल्द नहीं हटाया गया और समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आगे भी छात्राओं की तबीयत खराब हो सकती है। प्राचार्य ने प्रशासन से मामले में तत्काल ध्यान देकर कचरा हटाने और दुर्गंध की समस्या दूर कराने की मांग की है। इस संबंध में विधायक प्रताप ग्रेवाल से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका।

17 सितंबर से युवा धर्म संसद

उज्जैन। एआई के दौर में इंसान अपने विवेक, संवेदना और जिम्मेदारी को कैसे बचाए रखे? उज्जैन में 17 सितंबर से शुरू होने वाली तीन दिवसीय युवा धर्म संसद में इस सवाल पर महामंथन होगा। धर्म और संस्कृति के साथ एआइ, तकनीक, शिक्षा, रोजगार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक दायित्व और मानवीय मूल्यों पर चर्चा होगी। 24 राज्यों से 1700 से ज्यादा युवा इसमें शामिल होंगे।

सेवाज्ञ संस्थानम् के छठे संस्करण में छात्र, शोधार्थी, शिक्षक, संत, शिक्षाविद और सामाजिक चिंतक एक मंच पर होंगे, लेकिन संवाद का केंद्र युवाओं के सवाल रहेंगे। धर्म को पूजा-पद्धति और आस्था तक सीमित न रखकर कर्तव्य, आचरण, नैतिकता और लोकमंगल के संदर्भ में समझने का प्रयास होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान-तकनीक के बीच संवाद पर भी विचार किया जाएगा।

तकनीक की रफ्तार के बीच संवेदना का सवाल

एआई शिक्षा, रोजगार, कारोबार और रोजमर्रा के जीवन को बदल रहा है। सवाल उठेंगे कि तकनीक रोजगार बढ़ाएगी या पारंपरिक कामों का स्वरूप बदलेगी। शिक्षा में एआई शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध को कैसे प्रभावित करेगी? जब मशीनें जानकारी और विश्लेषण दे सकती हैं, तब इंसानी विवेक की भूमिका क्या होगी? सूचना की बाढ़ में सही-गलत की पहचान कैसे होगी? तकनीक के मानवीय और नैतिक प्रभावों पर भी चर्चा होगी।

स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के साथ परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का सवाल भी उठेगा। पर्यावरण, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सरोकारों पर युवाओं के दृष्टिकोण सामने आएंगे। उद्देश्य किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचाना नहीं, बल्कि विचार, तर्क और संवाद का अवसर देना है। 18 सितंबर को ह्यधर्म की अस्तित्वपरक अवधारणा एवं चारित्रिक उत्तरदायित्वह्ण और 19 सितंबर को ह्यऋषि एवं कृषि संस्कृति के मध्य भारत का आजीविका विचारह्ण विषय पर मुख्य सत्र होंगे। पहले दिन सूचना एवं विचार के संघर्ष तथा मनुष्य निर्माण में आस्था और धर्मस्थलों की भूमिका पर प्रश्नोत्तरी होगी। युवा वक्ताओं से सीधे सवाल भी कर सकेंगे।

टाटा डीईएफ के नाम पर नकली कारोबार का भंडाफोड़, नकली माल बरामद

वेब वार्ता, दतिया

जिले के जिगना थाना पुलिस ने सिकंदरा स्थित एक अवैध फैक्टरी पर कार्रवाई करते हुए टाटा डीईएफ (यूरिया) के नाम पर कथित रूप से नकली डीईएफ बनाने वाले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में टाटा डीईएफ के नाम से तैयार कथित नकली माल बरामद किया।

पुलिस ने मामले में कॉपीराइट अधिनियम के तहत जिगना थाने में एक आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। बताया गया है कि टाटा मोटर्स की ओर से अधिकृत बौद्धिक संपदा संरक्षण एजेंसी प्रोटेक्ट आईपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जांच अधिकारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।

सामग्री जब्त की शुरू की जांच

जांच के दौरान फैक्टरी से टाटा डीईएफ की खाली बाल्टियां, नकली बारकोड तथा नकली तरल तैयार करने में इस्तेमाल की जाने वाली यूरिया सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने बरामद सामग्री को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव का हुआ शुभारंभ

भोपाल। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाथियों के स्वास्थ्य, पोषण एवं समग्र कल्याण को समर्पित सात दिवसीय "हाथी महोत्सव" का शुभारंभ 14 सितंबर को कामती परिक्षेत्र के खरेर कैंप में फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा द्वारा किया गया। हाथी महोत्सव 20 सितंबर 2026 तक चलेगा। महोत्सव के दौरान सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 6 हाथियों को नियमित गश्ती एवं वन्यजीव प्रबंधन कार्यों से विश्राम देकर विशेष देखभाल प्रदान की जा रही है, जिसमें उन्हें उनकी पसंद के गन्ना, मक्का, नारियल एवं विभिन्न मौसमी फलों से युक्त पौष्टिक आहार देने के साथ प्रतिदिन नीम एवं अरंडी के तेल से मालिश की जाएगी। हाथी महोत्सव में सात दिनों के दौरान हाथियों का विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण, लंबाई एवं ऊंचाई का मापन तथा आवश्यकता अनुसार दांतों की ट्रिमिंग भी की जाएगी, जिसमें जबलपुर स्थित वन्यजीव स्वास्थ्य एवं फॉरेंसिक विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाएगा। महोत्सव में हाथियों के साथ वर्षों से समर्पित भाव से कार्य कर रहे महावत एवं चाराकटरों के स्वास्थ्य और उत्साह का भी विशेष ध्यान रखा गया है; उनका मेडिकल चेकअप कराने के साथ विभिन्न खेल एवं मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं तथा समापन दिवस पर कबड्डी एवं रस्साकशी प्रतियोगिताएं होंगी।

सर्वांगीण विकास, अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और जनकल्याण के लिए 42 हजार 490 करोड़ रुपए की स्वीकृति

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक संपन्न हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास, अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और जनकल्याण को गति देने के लिए 42 हजार 490 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के विस्तार के लिए केन्द्र प्रवर्तित 'समग्र शिक्षा योजना' की आगामी पांच वर्षों की निरंतरता के लिए 36 हजार 6 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की। नागरिक सुविधाओं में वृद्धि के उद्देश्य से परिवहन विभाग की 11 योजनाओं के लिए 1 हजार 166 करोड़ रुपये तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से उद्यानिकी विभाग की 8 योजनाओं के लिए 491 करोड़ रुपये की निरंतरता अनुमोदित की गई।

जल संसाधन के क्षेत्र में उज्जैन की चितावद, सिंगरौली की गौंड तथा अशोकनगर की चंदेरी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत किए गए, जिससे 1 लाख 27 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करते हुए नवगठित जिलों मैहर, मऊगंज और पांदुर्णा में खनिज शाखा की स्थापना के लिए 21 नवीन पदों तथा अनूपपुर व शहडोल के उन्नयित स्कूलों के लिए 36 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। साथ ही रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को 250 रुपये की अतिरिक्त विशेष सहायता दिए जाने का अनुसमर्थन और मार्कफेड को 2,220 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने केन्द्र प्रवर्तित योजना समग्र शिक्षा के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 36,006.22 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। समग्र शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान एवं विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों में वृद्धि करना, शाला शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक भेद को कम करना, शाला शिक्षा के सभी स्तरों पर समता एवं समावेशन सुनिश्चित करना, शाला शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना, शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्य को सहायता देना और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एस.सी.ई.आर.टी./राज्य शिक्षा संस्थान और डाइट को नोडल एजेंसियों के रूप में सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना है। साथ ही सार्व-भौमिक पहुंच, समता और गुणवत्ता, शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षक शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ किये जाने को इस योजना के मुख्य परिणामों के रूप में निर्धारित किया गया है। समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक अध्ययनरत 4 से 18 आयुवर्ग के समस्त श्रेणी के छात्र-छात्राओं की शिक्षा का प्रावधान है।

मंत्रि-परिषद ने परिवहन विभाग के सुचारू संचालन, अधोसंरचना विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार को ध्यान में रखते हुए विभाग अंतर्गत संचालित राजस्व एवं पूंजीगत व्यय सम्बंधी 500 करोड़ रुपए से कम की योजनाओं की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए कुल 1,166 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

स्वीकृति अनुसार उड़नदस्ता एवं चेक पॉइंट की स्थापना व्यय के लिए सर्वाधिक 377 करोड़ 41 लाख रुपये तथा जिला स्थापना व्यय के लिए 361 करोड़ 89 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा विभाग के मुख्यालय स्थापना व्यय के लिएभी 120 करोड़ 10 लाख रुपये और राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के संचालन के लिए 10 करोड़ 39 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। डिजिटल सेवाओं और अधोसंरचना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड योजना के निरंतर संचालन के लिए 245 करोड़ 55 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया है। विभागीय कार्यालय भवनों के नवीन निर्माण कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपये तथा मौजूदा परिसंपत्तियों के संधारण और रखरखाव के लिए लगभग 5.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

एम्स भोपाल का बड़ा कारनामा, 3डी प्रिंटिंग और पैर की हड्डी से बनाया कैंसर मरीज का नया जबड़ा

भोपाल। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एम्स) भोपाल के डाक्टरों ने जबड़े के कैंसर के एक जटिल मामले में थ्री-डी प्रिंटिंग तकनीक की मदद से सफल सर्जरी की है। मरीज के दाहिने निचले जबड़े में बड़ा ट्यूमर था।

डाक्टरों ने ट्यूमर निकालने के बाद मरीज के बायें पैर की फाइबुला हड्डी से नया जबड़ा तैयार किया। डाक्टरों ने चेहरे की बनावट और दांतों के सही मिलान को बनाए रखने के लिए पहले से तैयार थ्री-डी माडल और सर्जिकल गाइड का इस्तेमाल किया।

मरीज के थ्री-डी मॉडल पर मॉक सर्जरी की गई

खास बात यह रही कि ऑपरेशन से पहले मरीज के थ्री-डी मॉडल पर मॉक सर्जरी की गई। इसके लिए मरीज की सीटी स्कैन रिपोर्ट के आधार पर कंप्यूटर पर जबड़े की थ्री-डी तस्वीर तैयार की गई। फिर तय किया गया कि ट्यूमर को कहां से निकालना है और पैर की हड्डी को किस आकार में काटकर जबड़े में लगाना है। ऑपरेशन के एक महीने बाद जांच में हड्डी सामान्य रूप से जुड़ती मिली। चेहरे की बनावट भी काफी हद तक सामान्य हो गई। दांतों का मिलान सही है। वह सामान्य रूप से खाना चबा रहा है और बोल पा रहा है।

ट्यूमर निकालने की जिम्मेदारी शल्य आंकोलाजी विभागाध्यक्ष डा. विनय कुमार के नेतृत्व में निभाई गई। वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग और थ्री-डी प्रिंटिंग का काम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के डा. बाबूलाल सोनी और आथोर्पेडिक्स के डा. सौरभ कुमार सिन्हा ने संभाला। पुनर्निर्माण सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी टीम के डा. दीपक कृष्णा और डा. राहुल डुबेपुरिया ने की। संस्थान में ही वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग और थ्री-डी प्रिंटिंग की सुविधा का उपयोग जटिल सर्जरी में तकनीक आधारित उपचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे आपरेशन का समय और मरीज पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम करने में भी मदद मिल सकती है। - लेफ्टिनेंट जनरल (डा.) नरेंद्र कोतवाल (सेवानिवृत्त), कार्यपालक निदेशक, एम्स भोपाल।

क्या यह होती है वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग

जबड़े के बड़े ट्यूमर को निकाल कर हड्डी का हिस्सा दोबारा बनाना होता है। वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग में मरीज की सीटी स्कैन रिपोर्ट को कंप्यूटर पर थ्री-डी रूप में तैयार किया जाता है। डाक्टर पहले ही तय कर लेते हैं कि हड्डी को कहां से काटना है और नई हड्डी को किस तरह लगाना है। इससे आपरेशन के दौरान सर्जरी अधिक सटीक तरीके से की जा सकती है।

22 सितंबर को डोल ग्यारस पर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे भगवान कालभैरव

उज्जैन। भगवान महाकाल के सेनापति कालभैरव 22 सितंबर को डोल ग्यारस पर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। मंदिर की परंपरा अनुसार शाम 4 बजे राजसी वैभव के साथ सेनापति की सवारी नगर भ्रमण के लिए रवाना होगी। मंदिर प्रशासन द्वारा सवारी को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है।

मंदिर प्रशासक संध्या मार्कंडेय ने बताया मंदिर की परंपरा अनुसार शाम 4 बजे कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा पालकी में विराजित भगवान कालभैरव के रजत मुखारविंद व चरण पादुकाओं का पूजन कर पालकी को नगर भ्रमण के लिए रवाना करेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी सेनापति को गार्ड ऑफ ऑनर देगी। इसके बाद कारवां नगर भ्रमण के लिए रवाना होगा। सवारी में पुलिस का सशस्त्र बल, बैंड, धार्मिक झांकियां, अखाड़े, हाथी-घोड़े और भक्त शामिल होंगे। कालभैरव मंदिर से शुरू होकर सवारी नया बाजार, भैरवगढ़ नाका, माणक चौक, महेंद्र मार्ग होते हुए केंद्रीय जेल तिराहे पहुंचेगी।

यहां जेल अधीक्षक द्वारा भगवान की पालकी का पूजन किया जाएगा। इसके बाद सवारी सिद्धवट पहुंचेगी। यहां वैकुंठ द्वार पर पुजारी शिप्रा जल से बाबा कालभैरव और चरण पादुकाओं का पूजन करेंगे। इसके बाद सवारी ब्रजपुरा, जेल तिराहा होते हुए रात करीब 7.30 बजे वापस मंदिर पहुंचेगी।

साल में दो बार निकलती है कालभैरव की सवारी

भगवान कालभैरव को भगवान महाकाल का सेनापति और उज्जैन का नगर कोतवाल माना जाता है। वर्ष में दो बार उनकी सवारी निकलती है। पहली सवारी मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी यानी भैरव अष्टमी पर भगवान के जन्मोत्सव के अगले दिन तथा दूसरी भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी डोल ग्यारस पर निकलती है। दोनों सवारियों में भगवान चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं।

ग्वालियर से आएगी सिंधिया शाही की पगड़ी

पंडित संजय पुजारी ने बताया भगवान कालभैरव के लिए सिंधिया शाही की पगड़ी 22 सितंबर को ग्वालियर से विशेष वाहन द्वारा उज्जैन आएगी। राजवंश के उदय दर महाराज सिंधिया की ओर से पगड़ी लेकर उज्जैन पहुंचेंगे। 22 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे कलेक्टर पूजा अर्चना कर भगवान कालभैरव को पहले शाही पगड़ी धारण कर आएंगे इसके बाद सवारी निकलेगी।

12वीं के टॉपर्स ध्यान दें! *MP* में मुख्यमंत्री ई-स्कूटी योजना की राशि का किया दुरुपयोग तो होगी वसूली, हो सकती है एफआईआर

विदिशा। सरकारी स्कूलों में 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई ₹मुख्यमंत्री ई-स्कूटी, मोटराइज्ड वाहन योजना₹ में विद्यार्थी या पालक के खाते में आई रकम से स्कूटी खरीदना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो विभाग इस रकम की वसूली की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए पालक के विरुद्ध संबंधित थाने में एफआईआर भी कराई जा सकती है। राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ स्कूल के टॉपर विद्यार्थियों के लिए बनी स्कूटी योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं।

ई-स्कूटी के लिए अधिकतम 1.20 लाख रुपये की राशि तय

इसमें स्पष्ट कहा गया है कि पात्र विद्यार्थी पसंद का इलेक्ट्रिक वाहन चुन सकेगा। ई-स्कूटी के लिए अधिकतम 1.20 लाख रुपये व मोटराइज्ड वाहन के लिए अधिकतम 90 हजार रुपये की राशि तय की गई है। लेकिन इस राशि से कोई दूसरा वाहन नहीं खरीदा जाएगा। वाहन की निर्धारित राशि विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। विद्यार्थी का खाता नहीं होने पर राशि माता-पिता या अभिभावक के खाते में भेजी जाएगी। रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और एसेसरीज की राशि संबंधित वाहन विक्रेता को दी जाएगी।

राशि मिलने के बाद वाहन नहीं खरीदने पर सरकार सख्त

राशि उपलब्ध होने के बाद वाहन की खरीदी सुनिश्चित कराना जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। सरकार ने राशि मिलने के बाद वाहन नहीं खरीदने की स्थिति को भी गंभीरता से लिया गया है। ऐसे मामले में विद्यार्थी और उसके पालक के साथ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा वाहन नहीं खरीदने पर विद्यार्थी के अलावा पालक से राशि वसूली होगी। इसके साथ पुलिस थाने में एफआइआर तक दर्ज की जा सकती है। - एनके अहिरवार, जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा।

नए निर्देशों के अनुसार योजना के तहत खरीदा गया वाहन विद्यार्थी तीन साल तक न तो बेच सकेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकेगा। इसके लिए वाहन के पंजीयन के समय तीन साल की हाइपोथिकेशन दर्ज की जाएगी।

7500 को मिलेगी रकम

इस साल इस योजना से लाभान्वित होने वालों की संख्या 7500 से अधिक है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव 19 सितंबर को राजधानी के सुभाष उत्कृष्ट उमावि परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में यह रकम ऑनलाइन हस्तांरित करेंगे।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।